राष्ट्रपति 27 से 28 नवंबर तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगी

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोक शक्ति

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इंटरनेशनल आईडीईए की अध्यक्षता संभालेंगे

RNI Regn. No.7789/1964 | वर्ष-61 > अंक - 327 | रायपुर | गुरूवार 27 नवंबर 2025 विक्रम संवत 2082 | पृष्ठ 8 > मूल्य : 2 रू. | डाक पंजीयन : C.G/RYP DN/71/2023-25

नौसेना के सभी जहाज भारतीय शिपयार्ड्स में ही तैयार हो रहे हैं : रक्षा मंत्री राजनाथ

नई दिल्ली (पीआईबी)।

भारतीय नौसेना के 262 विभिन्न प्रोजेक्ट डिजाइन एवं विकास परियोजनाएं उन्नत चरणों में पहुंच चुकी हैं। खास बात यह है कि जहाज निर्माण व नौसेना की यह अन्य सभी परियोजनाएं स्वदेशी रूप से विकसित की गई हैं। यह बदलाव भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रमाण हैं। नौसैनिक क्षमता व स्वदेशीकरण की यह जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी।

वह मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित 'समुद्र उत्कर्ष' कार्यक्रम में बोल रहे थे। यहां उन्होंने समुद्री विरासत पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। 'समुद्र उत्कर्ष' सेमिनार के आयोजन का उद्देश्य भारत की उभरती हुई जहाज निर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करना है। इस कार्यक्रम में स्वदेशी शिपबिल्डिंग, नौसैनिक आधुनिकीकरण और समुद्री आत्मनिर्भरता पर विस्तृत चर्चा हुई। यहां रक्षामंत्री ने बताया कि कई भारतीय शिपयार्ड इस दशक के भीतर अपनी परियोजनाओं में 100 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री उपयोग करने की ओर अग्रसर हैं। इसका अर्थ है कि भारत से निर्मित किसी भी नौसैनिक प्लेटफॉर्म पर वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधानों का न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें गर्व है कि भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के सभी निर्माणाधीन जहाज भारतीय शिपयार्ड्स में ही तैयार हो रहे हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन का प्रत्यक्ष परिचायक है।

उन्होंने कहा कि विश्व के समुद्री इतिहास पर भारत की गहरी छाप है। हमारे पूर्वजों ने समुद्रों को बाधा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक संवाद के सेतु के रूप में इस्तेमाल किया। आज इस विरासत का सम्मान करते हुए भारत आगे बढ़ने के संकल्प के साथ कार्य कर रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों समुद्री तटों पर स्थित भारतीय शिपयार्ड अब आधुनिक फैब्रिकेशन लाइन्स, उन्नत मैटेरियल-हैंडलिंग सिस्टम्स, ऑटोमेटेड डिजाइन टूल्स, मॉडल टेस्टिंग सुविधाओं और डिजिटल शिपयार्ड तकनीकों से लैस हैं, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप हैं।

मोदी कैबिनेट बैठक में चार बड़े फैसले

रेयर अर्थ मैग्नेट विनिर्माण को बढ़ावा देगा भारत

ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर भारत काम करेगा

नई दिल्ली. एजेंसी ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार 26 नवंबर को बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कुल ?19,919 करोड़ रुपये की चार बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इन चार परियोजनाओं में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम भी शामिल है. इसके तहत तहत आने वाले 7 सालों में 7,280 करोड़ रुपये की रेयर अर्थ की खोज की जाएगी. इस स्कीम का मकसद इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना और हाई-टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है।

रेयर अर्थ मैग्नेट विनिर्माण योजना शामिल - भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा, इस पहल का मकसद भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करना है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत ग्लोबल आरईपीएम मार्केट में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर उभरेगा. मंत्रालय ने आगे कहा, आरईपीएम सबसे मज़बूत तरह के परमानेंट मैग्नेट में से एक हैं जो इलेक्ट्रिक गाडियों, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और डिफेंस एप्लीकेशन के लिए जरूरी हैं.

आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर सरकार का जोर - यह स्कीम इंटीग्रेटेड आरईपीएम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने में मदद करेगी, जिसमें रेयर अर्थ ऑक्साइड को मेटल में, मेटल को एलॉय में और एलॉय को फि निश्ड आरईपीएम में बदलना शामिल है. इस स्कीम में ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के ज़रिए पांच बेनिफिशियरी को टोटल कैपेसिटी देने का प्लान है. हर बेनिफि शियरी को 1,200 एमटीपीए तक की कैपेसिटी दी जाएगी।

ग्लोबल रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई चेन पर चीन का दबदबा होगा कम

वर्तमान समय में चीन ग्लोबल रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई चेन पर हावी है. उसने एक बेहद कड़े लाइसेंसिंग सिस्टम के जरिए जियोपॉलिटिकल पॉलिसी के टूल के तौर पर अपने कंट्रोल का इस्तेमाल किया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और गुजरात के कोस्टलाइन पर रेयर अर्थ डिपॉजिट हैं, गुजरात और महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाकों में भी ऐसा ही है. परमानेंट मैग्नेट हल्के और भारी रेयर अर्थ के कॉम्बिनेशन से बनाए जाएंगे. इन मिनरल को माइन, प्रोसेस और रिफाइन करना मुश्किल है।

मंत्री ने कहा, ट्रेड डील में भी रेयर अर्थ्स का जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक महत्व है. नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को भी हाल ही में दुनिया भर से मटेरियल सोर्स करने की मंजूरी दी गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि भारत आरईपीएम प्रोग्राम के जरिए ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर काम करेगा. ऑस्ट्रेलिया के पास रेयर अर्थ्स के बड़े भंडार हैं जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, जबकि जापानी प्रमुख टेक डेवलप कर रहे हैं।

पुणे मेट्रो का होगा विस्तार

पुणे मेट्रो का जल्द होगा विस्तार, कैबिनेट ने 9,857.85 करोड़ रुपये के बजट को दी मंजूरी पुणे के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में एक और बड़ी बढ़त मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 9,857.85 करोड़ रुपये है। पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के तहत लाइन 4 और लाइन को मंजूरी मिली है।

राबड़ी देवी के बाद तेज प्रताप यादव को भी खाली करना होगा आवास

एजेंसी

तेजप्रताप यादव की मां और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास छोड़ना होगा. उन्हें नया सरकारी आवास दिया गया है. सरकारी विभाग के आदेश के मुताबिक राबड़ी देवी को अब हार्डिंग रोड पर केंद्रीय पूल आवास में शिफ्ट किया गया. उन्हें यहां पर मकान नंबर 39 मिला है. यह घर उन्हें नेता प्रतिपक्ष के कोटे के तहत मिला, जबकि अभी तक 10 सर्कुलर रोड पूर्व मुख्यमंत्री कोटे का बंगला उनके ही नाम से मिला हुआ था. भवन निर्माण विभाग ने मंगलवार (25 नवंबर) को मंत्रियों और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए नए सरकारी आवासों का बंटवारा किया.बता दें कि राबड़ी देवी साल 2005 से 10 सर्कुलर रोड वाले आवास में रह रही थीं, लेकिन अब उन्हें इस घर को खाली करना पड़ेगा।

दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन, फरीदाबाद से आतंकी उमर का मददगार गिरफ्तार

नई दिल्ली एजेंसी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने लाल किले के बाहर 10 नवंबर को हुए कार बम विस्फोट मामले में फरीदाबाद के धौज निवासी सोयब को गिरफ्तार किया है। सोयब इस मामले में सातवां आरोपी है। जांच में सामने आया है कि उसने मुख्य आरोपी आतंकवादी उमर-उन-नबी को विस्फोट से ठीक पहले पनाह देने के साथ-साथ उसे लॉजिस्टिक सहायता भी मुहैया कराई थी।

इस धमाके में कई लोगों की मौत हुई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए थे। इससे पहले एनआईए उमर-उन-नबी के छह अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर चुकी है। सोयब की गिरफ्तारी से एजेंसी को मामले की कड़ी जोड़ने में अहम सफलता मिली है और जांच तेजी से आगे बढ़ी है।

संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान– राष्ट्रपति मुर्मू

संविधान दिवस पर सत्तापक्ष-विपक्ष में दिखी एकजुटता, समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी और राहुल गांधी

एजेंसी। संविधान दिवस के मौके पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल (जिसे अब संविधान सदन के नाम से जाना जाता है) में आयोजित कार्यक्रम में राजनीतिक दलों की एकता की झलक देखने को मिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई शीर्ष नेता एक ही मंच पर मौजूद रहे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति मुर्मू ने की. उनके साथ मंच पर उपराष्ट्रपति व राज्यसभा स्पीकर सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, प्रधानमंत्री मोदी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा के उस सभापति हरिवंश राय और संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू एक मंच पर मौजूद रहे.

संविधान दिवस के कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, 'हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है, ये औपनिवेशिक पहचान को त्याग करके राष्ट्रवादी भावना के साथ आगे बढ़ने का मार्गदर्शक ग्रंथ है. दंड के स्थान पर न्याय की भावना पर आधारित भारतीय न्याय संहिता को लागू किया गया है. ऐसे अनेक प्रगतिशील चीजों को सार्थक विमर्श के बाद पारित करने के लिए मैं संसद सदस्यों की सराहना करती हूं.'

सीएम रेखा गुप्ता ने 70 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया शुभारंभ

नई दिल्ली ,दिल्ली के नागरिकों को किफायती, सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज शक्ति नगर स्थित एमसीडब्ल्यू सेंटर (मातृत्व एवं शिशु कल्याण केंद्र) से 70 से अधिक 'आयुष्मान आरोग्य मंदिरों' का वर्चुअल तथा प्रत्यक्ष रूप से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इसे दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल बताया। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर नागरिकों को नियमित स्वास्थ्य जांच, आवश्यक एवं सामान्य दवाओं की निशुल्क उपलब्धता, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, जरूरी टीकाकरण कार्यक्रम, बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन संबंधी परामर्श तथा विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन टेली-परामर्श जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।

मुंबई एयरपोर्ट पर फर्जी पासपोर्ट के साथ नेपाली युवती गिरफ्तार, ओमान भागने का था प्रयास

एजेंसी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर इमिग्रेशन विभाग ने एक बड़ी फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया, जब एक नेपाली युवती भारतीय पासपोर्ट के साथ ओमान भागने की कोशिश कर रही थी। इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह घटना उस समय सामने आई जब काजल नाम की युवती मस्कत (ओमान) जाने वाली उड़ान 6ई 1267 में सवार होने के लिए इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंची। काउंटर पर तैनात इमिग्रेशन ऑफिसर रुचि रुपेश धोमकर को

युवती का व्यवहार और दस्तावेज संदिग्ध लगे। पासपोर्ट में उसका जन्मस्थान नौहरा, हिमाचल प्रदेश दर्ज था, लेकिन बातचीत और हाव-भाव से वह नेपाली नागरिक प्रतीत हो रही थी। शक के आधार पर उसे आगे की जांच के लिए इमिग्रेशन विंग के इंचार्ज के पास भेजा गया। पूछताछ के दौरान युवती ने स्वीकार किया कि उसका असली नाम काजल लामा है और वह नेपाल की निवासी है।

उसने बताया कि उसके माता-पिता नेपाल से हिमाचल प्रदेश आकर बसे थे और यहीं जन्म लेने के बाद उसने भारतीय पहचान बनाने के लिए आधार, पैन और अन्य दस्तावेज तैयार किए थे। इसके बाद, उसने शिमला पासपोर्ट कार्यालय से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवा लिया था।

युवती के मोबाइल फोन से प्राप्त दस्तावेजों ने उसकी सच्चाई का खुलासा किया।

विदेश | **प्रस्तावित समझौते पर बातचीत को जेलेंस्की तैयार**

पीस प्लान पर पुतिन के साथ चर्चा के लिए ट्रंप ने भेजे खास दूत

वाशिंगटन एजेंसी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्ति की कवायद तेज होती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 सूत्रीय समझौते को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ चर्चा के लिए अपने खास दूत को मास्को भेजा है। दूसरी ओर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी पीस प्लान पर चर्चा के मूड में नजर आ रहे हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, इस पीस प्लान पर फैसला करने की उम्मीद में, मैंने अपने स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ को मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मिलने का आदेश दिया है। दूसरी ओर, उसी समय पर सेना के सचिव डैन ड्रिस्कॉल यूक्रेन के

लोगों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, 28 प्वाइंट के वास्तविक पीस प्लान को दोनों तरफ से अधिक इनपुट के साथ फाइनल किया गया है। इस प्लान को अमेरिका ने ड्राफ्ट किया है। असहमति के कुछ प्वाइंट ही बचे हुए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ड्राफ्ट पर काम कर रहे लोगों की सरहना की और कहा कि उनकी टीम ने पिछले हफ्ते शानदार काम किया। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह जल्द ही पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलेंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ये मुलाकात तभी होगी, जब पीस प्लान पर दोनों की मुहर लग जाए या फिर वह आखिरी चरण में हो।

वहीं दूसरी ओर जेलेंस्की ने कहा कि जिनेवा में यूक्रेन और अमेरिका के तैयार किए गए पीस प्लान को और गहरे एग्रीमेंट में बदला जा सकता है। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन की नेगोशिएटिंग टीम के साथ प्लान पर चर्चा की थी।

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, इस ड्राफ्ट में दिए गए प्रिंसिपल्स को और गहरे एग्रीमेंट में बदला जा सकता है, और यह हमारे कॉमन इंटरेस्ट में है कि सुरक्षा वास्तविक हो। इंटरफैक्स-यूक्रेन न्यूज एजेंसी के अनुसार, इससे पहले, यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री यरमक ने कहा कि जेलेंस्की यूक्रेन संकट खत्म करने की शर्तों पर एक जॉइंट एग्रीमेंट को फाइनल करने के लिए ट्रंप से मिलना चाहते हैं।

पाकिस्तान में गायब हुए इमरान खान? जेल में सेहत बिगड़ने की अफवाहों से हड़कंप

21 दिन से नहीं मिल पा रहीं बहनें,

इस्लामाबाद एजेंसी।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सुरक्षा और सेहत को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है। रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान को लेकर मुल्क में तरह-तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। चिंता की बात यह है कि पिछले 21 दिनों से उनकी तीन बहनों और वकीलों को उनसे मिलने नहीं दिया गया है। कोर्ट से स्पष्ट अनुमति होने के बावजूद जेल प्रशासन ने मुलाकात पर रोक लगा रखी है, जिसके चलते अब उनके परिवार और समर्थकों में भारी आक्रोश है। इमरान की बहनों का आरोप है कि प्रशासन उनके भाई के ठिकाने और उनकी वास्तविक सेहत के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दे रहा है, जिससे अनहोनी की आशंका बढ़ गई

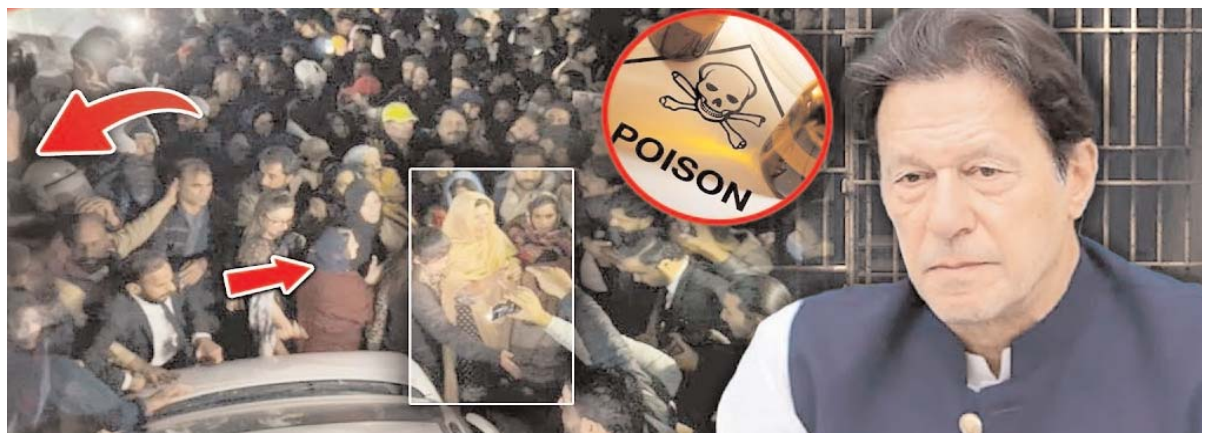

है। इमरान खान की बहन नौरीन ने इस मामले में पंजाब प्रांत के आईजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अदियाला जेल के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा किए गए 'बेरहमी से हमले' को लेकर आईजी को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। बहनों का कहना है कि उन्हें अपने भाई की सलामती की खबर तक नहीं मिल पा रही है और प्रशासन जानबूझकर उन्हें अंधेरे में रख रहा है। तीन हफ्ते बीत जाने के बाद भी कोई संपर्क न हो पाने के कारण पाकिस्तान की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और पीटीआई समर्थकों का गुस्सा सातवें आसमान पर है।

गौरतलब है कि क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में कैद हैं। उनकी गिरफ्तारी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (ह्वक) ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत की थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी बुशरा बीवी के साथ मिलकर रियल एस्टेट टायकून मलिक रियाज हुसैन से ट्रस्ट के नाम पर 60 एकड़ जमीन दान में ली थी, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।

इसी साल जनवरी 2025 में अदालत ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए इमरान खान को 14 साल और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा पूर्व पीएम पर कई अन्य गंभीर मामले भी चल रहे हैं। अब उनकी सेहत और लोकेशन को लेकर चल रही गोपनीयता ने पाकिस्तान की अस्थिर राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।

अफगानिस्तान के खोस्त में पाकिस्तानी हमले में 9 बच्चों की मौत : काबुल

काबुल एजेंसी

अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के एक रिहायशी इलाके में पाकिस्तानी सेना के हमले में नौ बच्चों समेत दस लोग मारे गए। अफगान सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार, यह हमला आधी रात के कुछ समय बाद हुआ और इसमें एक स्थानीय निवासी के घर को निशाना बनाया गया, जिससे सीमा पर दुश्मनी बढ़ने की चिंता फिर से बढ़ गई है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि यह हमला मंगलवार को सुबह करीब 12:00 बजे खोस्त के गुरबुज जिले के मुगलगई इलाके में हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हमलावर सेनाओं ने एक लोकल नागरिक, वालियत खान, काजी मीर

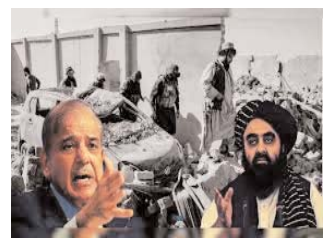

के बेटे के घर पर बमबारी की। इस हमले में 9 बच्चे (पांच लड़के और चार लड़कियां) और एक महिला की मौत हो गई और उनका घर तबाह हो गया। मुजाहिद ने यह भी बताया कि उसी रात कुनार और पक्तिका प्रांतों में अलग-अलग हवाई हमले हुए, जिनमें चार आम नागरिक घायल हो गए। खोस्त में हुआ ताजा हमला लोगों में डर पैदा कर रहा है कि पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच सीमा पर फिर से हिंसा का नया दौर शुरू हो सकता है।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

ग्राम सिंघोला से करमतरा-छुईखदान-सोनेसरार-खुर्सीपार तक पहुंच मार्ग जर्जर, राहगीर परेशान

लोकशक्ति

राजनांदगांव। जिले के ग्राम सिंघोला से करमतरा, छुईखदान, सोनेसरार होते हुए खुर्सीपार तक जाने वाला मुख्य ग्रामीण संपर्क मार्ग लंबे समय से बदहाल स्थिति में है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे रोजाना आवागमन करने वाले ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के समय यह मार्ग कीचड़ में तब्दील हो चुका था और अब सूखे मौसम में धूल की मोटी परत से राहगीर हलकान हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से सड़क की मरम्मत की मांग की जा रही है, लेकिन संबंधित विभाग एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र, रोजगार पर जाने वाले युवक एवं महिलाएं रोजाना जान जोखिम में डालकर इस मार्ग से आवाजाही करने मजबूर हैं।

*राजनांदगांवङ्कडोंगरगांव मुख्य मार्ग पर गड्ढों की भरमार, धूल में डूबे राहगीर**

राजनांदगांव से डोंगरगांव जाने वाला प्रमुख मार्ग भी अत्यंत जर्जर हो चुका है। अर्जुनी ग्राम के पास सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहनों का संतुलन बिगड़ने का खतरा बना रहता है। तेज रफ्तार वाहनों के गुजरते ही धूल का गब्बार उठता है, जिससे स्थानीय दुकानदार, व्यापारी और राहगीर लगातार परेशान हो रहे हैं। धूल के कारण आंख, नाक और सांस संबंधी समस्याएं बढ़ने की शिकायतें भी सामने आई हैं।

*अमलीडीह फैक्ट्री क्षेत्र में धूल का प्रकोप, राहगीर मानो रोज कर रहे ÷धूल-स्नान÷

अमलीडीह स्थित फैक्ट्री के पास धूल की स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है। सड़क के राइट साइड पर खड़े भारी वाहनों और जाम की स्थिति के बीच उनके पहियों से उ?ने वाली धूल पूरे क्षेत्र को ढक देती है। ग्रामीणों ने बताया कि धूल का इतना प्रकोप है कि राह चलते लोग मानो रोज ÷धूल-स्नान÷ करने मजबूर हैं। सड़क के बड़े-बड़े गड्ढों के बीच वाहन चलाना खतरे से खाली नहीं है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की सुस्त रवैया और बड़े उद्योगपतियों की सड़क पर कब्जेदार गाड़ियों ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। आसपास के रहवासियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है और व्यापारियों का भी रोजमर्रा का कामकाज बाधित है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से इन सभी सड़कों की तत्काल मरम्मत एवं धूल नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाने की मांग की है, ताकि वर्षों से झेल रहे इस कष्ट से उन्हें राहत मिल सके।

एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य के लिए बीएलओ तथा बीएलओ सुपरवाइजर सम्मानित

जिला निर्वाचन अधिकारी विनय लंगेह ने सरायपाली के बीएलओ को किया सम्मानित

महासमुंद, संवाददाता।

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। सरायपाली विधानसभा में भी एसडीएम सरायपाली सुअनुपमा आनंद (आईएएस) के मार्गदर्शन में एसआईआर की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। अभी सभी बीएलओ द्वारा गणना पत्रक वितरण कर घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना पत्रक भरवाकर बीएलओ एप में ऑनलाइन किया जा रहा है। उक्त कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुये मतदान केंद्र जटा कन्हार, केंद्र क्रमांक 207 के बूथ लेवल अधिकारी श्रीमती यमुना सिदार ने संपूर्ण जिले में 100 प्रतिशत फॉर्म डिजिटाइजेशन पूर्ण करने वाले प्रथम बीएलओ होने का गौरव प्राप्त किया। उनके इस उल्लेखनीय प्रदर्शन हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय लंगेह द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं शाल-श्रीफल से सम्मानित किया गया। इसी तरह से नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक फॉर्म डिजिटलाइजेशन की सराहनीय उपलब्धि

हासिल करने के लिए मतदान केंद्र बस्ती सरायपाली, केंद्र क्रमांक 136 के बीएलओ श्रीमती रेणुका साहू को भी कलेक्टर द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार संपूर्ण विधानसभा में सर्वाधिक फॉर्म डिजिटलाइजेशन करने की उपलब्धि प्राप्त करने हेतु मतदान केंद्र छिंदपाली, मतदान केंद्र क्रमांक 178 की बीएलओ श्रीमती उषा भाई को भी कलेक्टर लंगेह द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया एवं बीएलओ सुपरवाइजर विकास सिंह चंद्रा को भी अपने बीएलओ से उत्कृष्ट कार्य करवाने के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुअनुपमा आनंद तथा तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्रीधर पंडा, नायब तहसीलदार हरि प्रसाद भोई भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने उत्कृष्ट कार्य करने हेतु तहसील सरायपाली के संपूर्ण टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा भविष्य में और अच्छा कार्य करते हुए एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इससे प्रेरित होकर शेष बीएलओ भी अपने कार्य का समय सीमा में पूर्ण करें।

उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत ग्राम प्रभारी शिक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

07 दिसम्बर 2025 को आयोजित होगा महापरीक्षा अभियान

सुकमा, । जिले में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत आगामी 07 दिसम्बर 2025 को आयोजित होने वाले महापरीक्षा अभियान को लेकर ग्राम प्रभारी शिक्षकों का विकासखण्ड स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं उपाध्यक्ष मुकुन्द ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इसके तहत 19 नवम्बर 2025 को विकासखण्ड सुकमा, 21 नवम्बर को विकासखण्ड छिन्दगढ़ तथा 22 नवम्बर 2025 को विकासखण्ड कोन्टा में कुल 706 ग्राम प्रभारी शिक्षकों ने सहभागिता दर्ज कर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले के ग्रामीणों में साक्षरता के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पढ़ने-लिखने एवं समझने की क्षमता विकसित करना और समाज के असाक्षर वर्ग को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हे बुनियादी शिक्षा, गणितीय समझ एवं जीवनोपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनें और अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें।

प्रधानमंत्री का धन्यवाद जो वह जनजातीय समाज की चिंता कर रहे हैं - मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

रायपुर, छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रविवार को गोड समाज के युवक युवती एवं परिपक्तता विधवा सम्मेलन में शामील हुये मुख्यमंत्री ने कहा की इस आयोजन में मै शामील हुआ मै समाज का अभारी हु हमारे बोर्ड के चेयर मेन विकास मरकाम और गोड समाज के अध्यक्ष जग्गु सिंह मरकाम उपस्थित थे और इसमे अन्य प्रदेशो के लोग भी उपस्थित थे, अन्य प्रदेशो के बेटा बेटियो उपस्टिथत होकर अपना परिचय दिये और अपना नाम, पता दर्ज कराये है, यह सम्मेलन पिछले कई वर्षो से चल रहा है जो बहुत ही सराहनीय है, यह एक ऐसा मंच है जिसमे माता-पिता, वर-वधु उपस्थित होकर अपना परिचय देते है, गोड समाज एक समद्ध समाज है।

पुलिस हिरासत में बंद तोमर की जमानत याचिका खारिज

रायपुर, आरएनएस)। राजधानी में ब्याज पर धंधा करने वाले एवं गरीबों को लूटने वाले विरेन्द्र तोमर को पुलिस हिरासत में रखा गया है। विरेन्द्र ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए एक याचिका लगाई थी जिसके खारिज कर दिया गया है। ज्ञात रहे कि पुलिस ने तोमर बंधुओं को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था।उसे राजधानी लाया गया जहां पर उसका जुलूस निकाला गया। तोमन बंधूओं पहले अंडा ठेला चलाते थे, पश्चात ब्याज का धंधा किया, इसके अलावा लोगों से ऊंची दरों पर ब्याज वसूला। जिसको लेकर लोगों में रोष था। उसके विरूद्ध एफआईआर की गई, राजधानी में उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया।

किसान अब 25 नवंबर तक तहसील कार्यालय से करा सकते हैं धान बिक्री के लिए नवीन पंजीयन और रकबा संशोधन

०किसानों के हित में राज्य सरकार का अहम फैसला, किया गया अतिरिक्त समय का प्रावधान

सहयोग के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 जारी

सुकमा, खरीफ वर्ष 2025 अंतर्गत किसानों को धान बेचने में सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एकीकृत किसान पोर्टल में शेष कृषक, डूबान, वन पट्टाधारी कृषकों के कैरीफारवर्ड नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन की कार्यवाही हेतु 25 नवंबर 2025 तक अतिरिक्त समय का प्रावधान किया है। किसान इसके लिए अपने संबंधित तहसील कार्यालय में जाकर पंजीयन और रकबा संशोधन का कार्य करा सकते हैं। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने समस्त एसडीएम, तहसीलदारों सहित सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उल्लेखनीय है कि खरीफ वर्ष 2025 में एकीकृत किसान पोर्टल के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन की कार्यवाही 01 जुलाई से 31 अक्टूबर 2025 तक करने का निर्देश जारी किया गया था। किन्तु किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकीकृत किसान पोर्टल में शेष कृषक, डूबान, वन पट्टाधारी कृषकों के कैरीफारवर्ड नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल रकबे में संशोधन के लिए 19 नवंबर से 25 नवंबर तक एक सप्ताह अतिरिक्त समय का प्रावधान पोर्टल के तहसील लॉगिन में किया गया है। इसके साथ ही किसानों को पंजीयन में यदि किसी प्रकार की समस्या या तकनीकी समाधान की आवश्यकता हो तो एग्रीस्टेक हेल्पडेस्क के टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर कॉल कर के सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

बटमूल कॉलेज महापल्ली में हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान थीम के अंतर्गत मनाया गया संविधान दिवस

महाविद्यालय परिसर की साफसफाई करते हुए मनाया गया संविधान दिवस

लोकशक्ति

रायगढ़- संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हुए संविधान के उद्देशिका का वाचन किया जाता है इसी परिप्रेक्ष्य में शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के रासेयो प्रकोष्ठ के समन्वयक डॉ रविंद्र चौबे एवं जिला संगठक भोजराम पटेल के निर्देशानुसार बटमूल आश्रम महाविद्यालय साल्हेओना महापल्ली के चेयरमेन श्री एन आर प्रधान, प्राचार्य डॉ. पी एल पटेल जी, वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो पी के कापड़ी एवं प्रो पी के गुप्ता के मार्गदर्शन तथा कार्यक्रम अधिकारी रासेयो सह रेडरिबन व रेडक्रॉस प्रभारी डॉ के के गुप्ता के कुशल नेतृत्व में 26 नवंबर 2025 को महाविद्यालय में भारतीय संविधान के उद्देशिका का

सामूहिक वाचन किया गया। रासेयो प्रभारी डॉ के के गुप्ता ने ÷हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान÷ थीम के अंतर्गत संविधान दिवस की आयोजन के बारे में बताते हुए विश्व के सबसे बड़े संविधान के विशेषताओं को बताया। तत्पश्चात प्रभारी प्राचार्य प्रो पी के कापड़ी द्वारा महाविद्यालय संचालन समिति के अध्यक्ष एन आर प्रधान की उपस्थिति में महाविद्यालय के स्टाफएवं स्वयंसेवकों को सामूहिक रूप से उद्देशिका का वाचन कराया गया। साथ ही भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखने तथा भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखने की सामूहिक शपथ ली गई। उसके बाद स्वयंसेवकों द्वारा महाविद्यालय परिसर एवं बागवानी की साफ सफाई करते हुए स्वच्छता अभियान का संदेश दिया। इस अवसर पर महाविद्यालय संचालन समिति के अध्यक्ष एन आर प्रधान, सचिव दशरथ गुप्ता, कोषाध्यक्ष रमेश गुप्ता, वरिष्ठ प्राध्यापक प्रो पी के कापड़ी, प्रो पी के गुप्ता, डॉ विक्रांत गुप्ता, रासेयो कार्यक्रम अधिकारी डॉ. के के गुप्ता, डॉ गीता देवांगन, प्रो नीलकंठ निषाद,प्रो प्रज्ञा विश्वाल, प्रो स्मिता पण्डा, प्रो लक्ष्मीन खड़िया, प्रो सुधा पटेल, निशांत पण्डा, श्रीमती अनुप्रिया गुप्ता, त्रिलोचन बरेठ, यमुना मेहर, सुमन किसान, सुशीला यादव एवं महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी रही।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर निगम सख्त, सार्वजनिक संस्थानों में आवारा कुत्तों की रोकथाम के लिए कड़े सुरक्षा उपाय लागू

दुर्ग, संवाददाता।

सुप्रीम कोर्ट के सुओ-मोटो निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिक निगम दुर्ग ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने हेतु महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले परिसरों में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।

निगम क्षेत्र के सभी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, स्टेडियमों, खेल परिसरों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में बाउंड्री वॉल, फेंसिंग, मुख्य गेट, सीसीटीवी कैमरे और आवश्यक सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था अनिवार्य की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को भी सख्ती से लागू

किया जाएगा, ताकि कुत्तों को भोजन या ठहरने का अवसर न मिले। नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी तय प्रत्येक संस्थान में एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा, जो– ङ्क परिसर में आवारा कुत्तों की रोकथाम ङ्क सफाई और कचरा निपटान की निरंतर निगरानी ङ्क आवश्यक ढांचागत सुधार की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार रहेगा। नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन 1100 संस्थान के मुख्य द्वार पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

निगम ने निर्देश जारी किए, लापरवाही पर कार्रवाई होगी निगम प्रशासन ने सभी संबंधित संस्थानों को पत्र भेजकर पालन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि सुरक्षा और स्वच्छता मानकों की अवहेलना करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह कदम बच्चों, मरीजों, खिलाड़ियों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की घटना या असुविधा से बचा जा सके।

13 दिसंबर को आयोजित होगी वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत

तैयारियों को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ली अहम

सूरजपुर, लोकशक्ति।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दिशा-निर्देशानुसार, वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 13 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। इस महाअभियान को सफल बनाने और आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। यह बैठक अध्यक्ष/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती विनीता वार्नर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लोक अदालत की तैयारियों पर गहन चर्चा की गई।

दो पालियों में संपन्न हुई समीक्षा बैठक लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु यह बैठक दो अलग-अलग पालियों में आयोजित की गई। प्रथम पाली में राजस्व व प्रशासनिक अमले के अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। इस सत्र में अपर कलेक्टर जगरनाथ वर्मा सहित जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी(स्छरू) और

कार्यकारी मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) शामिल हुए। इसमें राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण पर जोर दिया गया। द्वितीय पाली पुलिस अमले के अधिकारी शामिल हुए। दूसरे सत्र में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (स्क्) प्रशांत कुमार ठाकुर, सभी थाना प्रभारी और यातायात प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक के मुख्य बिंदु और उद्देश्य बैठक के दौरान लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक पक्षकारों को लाभ पहुँचाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर रणनीति तैयार की गई। प्रकरणों का चिन्हांकन-जिला न्यायालय, तालुका न्यायालय, कुटुंब न्यायालय और सभी राजस्व न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर लोक अदालत में रखने के निर्देश दिए गए। प्री-लिटिगेशन प्रकरण मुकदमा शुरू होने से पहले के मामलों (Pre-litigation) पर विशेष जोर दिया गया। इसमें शामिल हैंरू पारिवारिक विवाद और जमीन संबंधी लड़ाई-झगड़े। वित्तीय सेवाओं से जुड़े मामले (बैंक लेनदेन, बिजली बिल, पानी और फोन बिल आदि)। जन-जागरूकता बैठक में इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि लोक अदालत के फायदे और आयोजन की जानकारी जिले के अंतिम नागरिक तक कैसे पहुंचाई जाए, ताकि ग्रामीण अंचल के लोग भी इसका लाभ उठा सकें। लक्ष्य जिला एवं राज्य शासन के विभागों की निगरानी में वित्तीय सेवाओं से संबंधित प्री-लिटिगेशन मामलों में पक्षकारों को इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत में अधिकतम राहत प्रदान करना।ये रहे उपस्थित इस विशेष परिचर्चा और समीक्षा बैठक में न्यायिक, प्रशासनिक और पुलिस विभाग के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता श्रीमती विनीता वार्नर (अध्यक्ष/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश) ने की।

न्यायिक अधिकारी मानवेंद्र सिंह (प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश), डी.एस. बघेल (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), सुपायल टोपनो (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) बैठक में उपस्थित रहे।

धान खरीदी व्यवस्था सुव्यवस्थित करने नवीन टोकन व्यवस्था

भूमि श्रेणी के अनुसार टोकन जारी

टोकन तुहर ऐप से घर बैठे ले सकते हैं सुविधा का लाभ

महासमुंद, लोकशक्ति। । राज्य शासन के निर्देशानुसार धान खरीदी प्रणाली को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित तरीके से संचालित किए जाने हेतु इस वर्ष टोकन जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा किसान हितैषी बनाया गया है। किसानों की सुविधा के लिए नवीन टोकन व्यवस्था लागू करते हुए निर्धारित पात्रता के आधार पर टोकन जारी किए जा रहे हैं।

शासन द्वारा जारी व्यवस्था के अनुसार 2 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को अधिकतम 1 टोकन, 2 से 10 एकड़ तक के कृषकों को अधिकतम 2 टोकन तथा 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को अधिकतम 3 टोकन की पात्रता निर्धारित की गई है।

किसानों की सहूलियत को ध्यान में

रखते हुए राज्य शासन ने टोकन तुहर ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके माध्यम से कुल उपलब्ध टोकनों में से 80 प्रतिशत टोकन लघु एवं सीमांत किसानों के लिए तथा 20 प्रतिशत टोकन दीर्घ किसानों के लिए आरक्षित किए गए हैं। किसान अपनी सुविधानुसार ऐप में लॉगिन कर निर्धारित मानदंडों के अनुसार टोकन प्राप्त कर सकते हैं।

किसानों द्वारा आवेदन करने की तिथि से अगले सात खरीदी दिवस तक का टोकन जारी किया जा सकता है।

सपने देखें, संकल्प लें, धारा के विपरीत मेहनत कर आगे बढ़ें-आनंद कुमार

रायपुर।

कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम में उमड़ा उत्साह आनंद कुमार और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने युवाओं को दिया सफलता का मंत्र ।वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के पहल पर सरिया में आयोजित कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम में सुपरङ्क30 के संस्थापक पद्मश्री आनंद कुमार ने हजारों युवाओं को प्रेरणा से भर दिया। स्कूल मैदान में 3 हजार से अधिक युवा, शिक्षक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। पूरा मैदान युवाओं की तालियों और फ्लैशलाइट की रोशनी से गूंज उठा।

मुख्य अतिथि आनंद कुमार ने छात्रों से कहा कि जीवन में बड़ा सपना देखें और उसे पूरा करने के लिए संकल्प और निरंतर मेहनत करें।उन्होंने कहा कि ÷जीवन में जितनी मुश्किलें आएंगी, सफलता उतनी बड़ी होगी। पढ़ाई मेहनत से होती है, पैसे से नहीं। शिक्षक नौकरी समझकर नहीं, बल्कि यज्ञ और जिम्मेदारी की भावना से पढ़ाएं।÷अपनी संघर्ष यात्रा बताते हुए उन्होंने कहा कि कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में चयन होने के बाद भी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे नहीं जा पाए। पिता के निधन के बाद पापड़ बनाकर और बेचकर पढ़ाई जारी रखी।ज़रूरतमंद बच्चों के लिए सुपर-30 शुरू किया और विक्कीङ्कभोलू जैसे कैरेक्टरों के जरिए बच्चों को पढ़ने के विभिन्न तरीके सिखाए।

उन्होंने बताया कि कोचिंग माफ़ियाओं ने पांच बार उन पर हमला करवाया, धमकियां भी मिलीं, लेकिन वे रुके नहीं।केबीसी में अमिताभ बच्चन द्वारा 25 लाख की मदद, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा जीवनी का लोकार्पण और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री सम्मान का उल्लेख कर उन्होंने कहा-आज यहाँ का कोई बच्चा भविष्य में अवार्ड लेकर कहे कि उसे प्रेरणा सरिया में मिले इस कार्यक्रम से मिली, वही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा।÷वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने युवाओं से कहा कि मजबूत इरादा किसी भी बाधा को पार करा सकता है।

फिल्म 'सुपर-30' का प्रसिद्ध संवाद उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा—÷जब समय आएगा, सबसे ऊंची छलांग हम ही लगाएंगे।÷उन्होंने तमिलनाडु की एक युवती की प्रेरक कहानी साझा करते हुए कहा कि हर बच्चा अपने घर की परिस्थिति के हिसाब से कैरियर चुने, किसी दबाव में नहीं।÷सिंसियर बनें, सही कोर्स चुनें और अभी से अपना प्लान तय करें। यूट्यूब चैनल पर आईएएस विजन संबंधी वीडियो देखें, यह आपके लिए उपयोगी होगा।÷चौधरी ने अपने संघर्ष के दिनों की कहानी भी सुनाई— गांव से लेकर दिल्ली तक आईएएस की किताबों की खोज और विपरीत परिस्थितियों में पढ़ने का किस्सा युवाओं को बेहद प्रेरित कर गया।कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे, पूर्व विधायक श्री विजय अग्रवाल, रायगढ़ मेयर श्री जीववर्धन चौहान, विभिन्न पदाधिकारी और गणमान्य नागरिकों सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम में सीजीपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों, कक्षा 10वीं-12वीं के मेधावी विद्यार्थियों सहित 100 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया।वित्त मंत्री ने सभी सम्मानित बच्चों को 5-5 हजार रुपये स्वेच्छानुदान देने की घोषणा की, जिसका युवाओं ने जोरदार स्वागत किया।युवाओं को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने घोषणा की÷प्रदेश का कोई भी युवा यूपीएससी प्री परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, उसे 1 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।÷सरिया में आयोजित यह भव्य कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम युवाओं के लिए प्रेरणा, ऊर्जा और नए संकल्पों का संगम साबित हुआ।

सूर्य नगर में प्रार्थना सभा को लेकर बवाल, जबरन मतांतरण के आरोप में महिला पास्टर सहित तीन गिरफ्तार

रायपुर, ।

प्रदेश में लोगों को लालच देकर या बहला-फुसलाकर धर्म बदलवाने के आरोपों से जुड़ी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन भी सक्रिय होकर कार्रवाई कर रहा है। रविवार को प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जबरन मतांतरण की कोशिश से जुड़े तीन मामलों में कार्रवाई की गई, जिनमें कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार व्यक्तियों में एक महिला पास्टर भी शामिल है।

दुर्ग का मामला - घटना दुर्ग जिले की बताई गई है। भिलाई के नेवई थाना क्षेत्र के सूर्य नगर में एक मकान में प्रार्थना सभा आयोजित किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वहां घर को चर्च की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था और प्रार्थना सभा के माध्यम से मतांतरण की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं और साहू समाज के लोगों ने घर के बाहर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की।

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला पास्टर समेत तीन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आरोपितों पर धारा 299 बीएनएस, धारा 3(5) तथा छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्रवाई की गई है।

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपितों के नाम मनोज कुमार साहू, उनकी पत्नी तथा पास्टर मालती साहू और रविशंकर चंदेल हैं। पुलिस के अनुसार घटना के दौरान सुबह 11 बजे से बड़ी संख्या में लोग घर के सामने इकट्ठा हो गए थे। प्रदर्शन करने वालों ने दावा किया कि घर में 30-40 लोग प्रार्थना कर रहे थे और आरोप यह भी लगाया गया कि साहू दंपती ने कुछ वर्ष पहले धर्म परिवर्तन किया था और अब आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं।

जमीन की सरकारी कीमत मार्केट रेट से ज्यादा, कांग्रेस जनों ने किया पंजीयन कार्यालय के सामने जंगी प्रदर्शन

पंजीयन शुल्क को 4 प्रतिशत रखने की मांग

0 जांच कराकर नया रेट लागू करना चाहिए

रायपुर, राज्य शासन के द्वारा जमीन की नई रजिस्ट्री दर लागू करने के विरोध में आज कांग्रेसजनों ने जिलाधीश कार्यालय में जंगी प्रदर्शन किया।

रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय द्वारा मिली जानकारी के अनुसार राज्य में आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर जमीन की नई रजिस्ट्री दरें लागू की गई है, जिसके कारण बिल्डरों एवं गरीबों में काफी रोष है। जिसके कारण यहां पर जमीन की खरीदी बिक्री प्रभावित होगी। वहीं चोर दरवाजा भी खुल जाएगा जिसके चलते यहां शासन को घाटा होगा वहीं शासन को राजस्व की क्षति होगी। उपाध्याय ने आरोप लगाया कि राज्य में डायवर्सन नहीं होने से वैसे भी गरीब लोग और किसान परेशान है। इस तरह नई रजिस्ट्री के रेट जारी होने से लोग परेशान हो जाएंगे। आज जिला पंजीयन एवं स्टाम्प कार्यालय के सामने विकास उपाध्याय सहित जिलाध्यक्ष एवं विभिन्न पदाधिकारियों ने भाग लिया। यहां पर लोगों ने सरकार के विरूद्ध जमकर नारे बाजी की है। याद रहे कि राजधानी में इस समय बड़ी संख्या में बिल्डर सक्रिय है। नए रेट के बढ़ाने से यहां पर लोग परेशान हो जाएंगे। वैसे भी रजिस्ट्री कराने के लिए काफी परेशानी लोगों को होती है।

इधर बिल्डरों ने आरोप लगाया कि कई जगहों में जमीन की सरकारी कीमत मार्केट रेट से ज्यादा हो गई है। जितने में लोग जमीन खरीदेंगे उससे ज्यादा रजिस्ट्री शुल्क देंगे। इसका सीधा असर रियल स्टेट पर पड़ेगा। पहले 1500 से ज्यादा जगहों की आधार मानकार जमीन की गाइड लाइन की जाती थी लेकिन इसकी संख्या घटकर संख्या 700 के आसपास रह गई है। क्रेडाई के सदस्यों ने ओपी चौधरी से मुलाकात की और कहा कि जिन जगहों पर सरकारी कीमत बाजार रेट से ज्यादा हो गई है वहां जांच करवाकर नया रेट लागू किया जाए। कलेक्टर ने गाइड लाइन में 30 प्रतिशत छूट को पहले ही समाप्त कर दिया है। इसलिए गाइड लाइन में लगने वाली पंजीयन शुल्क की दर वर्तमान में नई गाइड लाइन लागू किया जाना चाहिए। जिससे आवासीय तथा व्यापारिक इमारतों पर बिक्री मूल्य कम होगा।

अमीन भर्ती परीक्षा के लिए व्यापम ने जारी किए दिशा-निर्देश

मोहला संवाददाता।

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा जल संसाधन विभाग अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा 07 दिसंबर 2025 को राज्य के 16 जिलों में आयोजित की जाएगी। जिसके अनुसार परीक्षा का समय पूर्वाहन 12:00 बजे से 2:15 बजे तक निर्धारित है।

व्यापम ने परीक्षा के सुचारू संचालन और परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिनका पालन सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। निर्देशों के अनुसार परीक्षार्थियों को परीक्षा से एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र का अवलोकन कर लेना होगा तथा परीक्षा वाले दिन कम से कम दो घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना आवश्यक होगा। परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पूर्व, अर्थात 11:30 बजे, केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा।

- व्यापम द्वारा जारी ड्रेस कोड करना होगा पालन

व्यापम ने ड्रेस कोड भी अनिवार्य किया है, जिसके तहत अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनने होंगे और काला, गहरा नीला, गहरा हरा, जामुनी, मैरून,

बैगनी व गहरा चॉकलेट रंग पहनना प्रतिबंधित रहेगा। बिना पॉकेट वाला साधारण स्वेटर अनुमति योग्य होगा, जिसकी सुरक्षा जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक में आने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा और अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा। - संचार उपकरण सहित ये रहेंगे प्रतिबंधित

परीक्षा में परीक्षार्थियों को फुटवियर के रूप में केवल चप्पल पहनने की अनुमति दी गई है, वहीं कान में किसी भी प्रकार का आभूषण पहनना वर्जित है। परीक्षा कक्ष में मोबाइल, संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। अनुचित साधन के उपयोग पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है। अभ्यर्थियों को केवल काले या नीले बॉल पेन साथ लाने की अनुमति होगी। व्यापम ने अपील की है कि सभी परीक्षार्थी समय पर पहुंचे और दिशा-निर्देशों का पालन करें ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

शास्त्रीय चौक से जयस्तंभ तक एकांकी मार्ग

एक माह के लिए घोषित
जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

रायपुर, राजधानी में स्काई वॉक का निर्माण कार्य प्रारंभ है। वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं दंडाधिकारी ने निर्देश दिया है कि शास्त्री चौक से मेकाहारा चौक तक तथा शास्त्री चौक से मल्टीलेवल पार्किंग तक जयस्तंभ चौक की ओर रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक एक माह तक एकांकी मार्ग होगा। प्रथम 15 दिन में शास्त्री चौक से मल्टीलेवल पार्किंग तक जयस्तंभ चौक की ओर मार्ग तथा अगले 15 दिन में शास्त्री चौक से मेकाहारा चौक तक एकांकी मार्ग होगा। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि एकांकी मार्ग किए जाने के लिए बंद मार्ग को प्रवेश एवं निर्गम स्थान पर पर्याप्त संख्या में रिफ्लेक्टिव बेरिकेट्स लगाकर बंद करेंगे। वाहनों को परिवर्तित करने एवं यातायात संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में गार्ड्स की व्यवस्था करेंगे ।

रायपुर पहुंचे सचिन पायलेट, कहा-जल्द होंगे जिला अध्यक्षों के नाम घोषित

रायपुर (संवाददाता)।

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने मंगलवार को कहा कि पार्टी संगठन में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस को एक नई टीम और नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतारने की तैयारी है।

सचिन पायलट ने नवा रायपुर में होने वाले ष्ठत्र कॉन्फ्रेंस पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा साय सरकार पहले अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभाल ले, फिर इस तरह के बड़े आयोजन कराए। पायलट ने हाल के अपराधों और प्रदेश में बढ़ती असुरक्षा पर भी चिंता जताई।

कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट आज से दो दिवसीय बस्तर दौरे पर हैं। उनके साथ तीनों प्रभारी सचिव भी मौजूद रहेंगे। दौरे के दौरान पार्टी स्ढ्ढक्र महंगी बिजली, धान खरीदी सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति

तैयार करेगी। आज धमतरी और कांकेर में बैठक होगी, जबकि कल जगदलपुर में संगठन की समीक्षा और रोडमैप तैयार किया जाएगा। इस दौरान PCC चीफदीपक बैज भी मौजूद रहेंगे।

SIR में भारी गड़बड़ी, वैध मतदाताओं का नाम कटना बर्दाश्त नहीं

संविधान दिवस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि कांग्रेस संविधान के प्रति आस्था और लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से संविधान दिवस मना रही है।

उन्होंने राज्य में चल रहे SIR (मतदाता सूची पुनरीक्षण) को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। पायलट ने कहा कि SIR के नाम पर SIR पर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि कई SIR आत्महत्या तक कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस फर्जी मतदाता सूची में नहीं चाहती लेकिन वैध मतदाता का नाम कटना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सचिन पायलट ने निर्वाचन आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के प्रमाण पेश किए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यदि संविधान के विरुद्ध कोई काम करेगा, तो कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध करेगी।

14 दिसंबर को होगा बड़ा आंदोलन

पायलट ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार दो दिनों तक बैठक करे ब्लॉक को प्रशिक्षित करेगी, ताकि स्ढ्ढक्र की प्रक्रिया में गड़बड़ियों को रोका जा सके। वहीं, 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में स्ढ्ढक्र में गड़बड़ी के विरोध में बड़ा आंदोलन आयोजित किया जाएगा।

रायपुर के आसमान में दिखी चमकदार कतार, लोगों में कौतूहल—स्टारलिंक सैटेलाइट निकला कारण

रायपुर, राजधानी में रविवार शाम आसमान में दिखाई दिया अनोखा नजारा चर्चा का विषय बन गया। शहर के कई इलाकों में लोगों ने आकाश में चमकते बिंदुओं की लंबी श्रंखला को एकसाथ आगे बढ़ते देखा, जो कुछ देर बाद धीरे-धीरे ओझल हो गई। अचानक दिखाई दी इस रोशनी ने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का ध्यान खींच लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चमकदार कतार बिल्कुल ट्रेन के डिब्बों जैसी प्रतीत हो रही थी। उत्सुक लोगों ने मोबाइल फोन से वीडियो और तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दीं। इसके बाद तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं—किसी ने इसे स्नह्न से जोड़ा, तो किसी ने इसे बाहरी ग्रहों से जुड़ी गतिविधि माना। बाद में विशेषज्ञों द्वारा स्पष्ट किया गया कि आसमान में दिखाई दी यह रोशनी किसी रहस्यमयी घटना का नहीं, बल्कि एलन मस्क की स्टारलिंक परियोजना के सैटेलाइट्स का परिणाम था।

नवाचार का उत्सवः कलिंगा विश्वविद्यालय में साइंस वर्किंग मॉडल प्रतियोगिता 4.0 का आयोजन संपन्न

लोकशक्ति

कलिंगा विश्वविद्यालय, नया रायपुर ने 22 नवम्बर 2025 को साइंस वर्किंग मॉडल प्रतियोगिता 4.0 का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसने पूरे छत्तीसगढ़ से उत्कृष्ट वैज्ञानिक प्रतिभाओं को एक मंच पर लाया और नवाचार, शोध संस्कृति तथा समग्र छात्र विकास के अग्रणी केंद्र के रूप में विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। 40 से अधिक स्कूलों, 80 कार्यरत वैज्ञानिक मॉडलों, 400 से अधिक प्रतिभागी छात्र और 450+ विज़िटर्स के भागीदारी के साथ, इस आयोजन ने रचनात्मकता और जिज्ञासा का एक उत्साहजनक वातावरण बनाया।

कार्यक्रम का उद्घाटन कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. संदीप गांधी द्वारा किया गया, जिन्होंने भाग लेने वाले छात्रों की मौलिकता, रिसर्च ओरिएंटेशन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की

सराहना की, और उन्हें राष्ट्र-निर्माण में योगदान देने वाले नवाचारपूर्ण तथा भविष्य-उन्मुख विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। मॉडलों के मूल्यांकन पैनल में कलिंगा विश्वविद्यालय के डॉ. अंजनियुलु बेंदी, उप अधिष्ठाता- अकादमिक मामलों तथा प्रभारी अधिष्ठाता- विज्ञान संकाय; डॉ. सुष्मा दुबे, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जैव प्रौद्योगिकी विभाग; डॉ. प्रीति पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग; तथा डॉ. अलोक वर्मा, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, भौतिकी विभाग शामिल थे।

छात्रों और विद्यालयों को विज्ञान प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट प्रयासों और नवाचार के लिए आकर्षक नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। विजेता मॉडल जिन्होंने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया :-

कृष्णा पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल (लक्ष्मी सेन, सानिध्य नायक) द्वारा ÷ग्रो योर माइक्रोग्रीन्स÷ ने ?5000 के साथ आउट ऑफ़ द बॉक्स थिंकर पुरस्कार जीता ।

भारत माता स्कूल, नया रायपुर (आशीष) के ÷डेस्कटॉप असिस्टेंट÷ ने ?5000 के साथ क्यूरियस माइंड पुरस्कार जीता। आदर्श इंटरनेशनल, नया रायपुर (ऋषभ देशमुख, मयंक शर्मा, प्रिंसी बारले, मेनका साहू, हिमानी धुर्वे) द्वारा ÷हार्मलेस सोलर एनर्जी÷ ने ?5000 के साथ वैज्ञानिक सिद्धांतों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पुरस्कार जीता। जे.बी. पब्लिक स्कूल के ÷पावर रक्षक÷ (पूरब निषाद, लकी ध्रुव, पुष्कर वर्मा) ने ?5000 के साथ मोस्ट प्रॉमिसिंग इनोवेटर्स पुरस्कार जीता।

संत ज्ञानेश्वर विद्यालय (पूर्वी साहू, गुरवंश साहू, वर्षा परिदा) की ÷फ्लोईज़÷ ने ?5000 के साथ सर्वश्रेष्ठ शिल्प कौशल पुरस्कार जीता।

नुवोको पब्लिक स्कूल, बिलासपुर (सैयद काशिफ अली) द्वारा ÷रीह्यूम जेन÷ ने ?10,000 के साथ बेस्ट आइडिया इन एक्शन पुरस्कार जीता।

होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल (शौर्या सिंह, प्रियांशु सिंह) द्वारा ÷महिलाओं और बच्चों की स्वच्छता के लिए सौर स्वच्छता किट÷ ने ?12,000 के साथ युवा आविष्कारक पुरस्कार जीता; और दावरा इंटरनेशनल स्कूल, अभनपुर (प्रियांशु निर्मलकर, पीयूष प्रजापति, पूर्वा टंडन, श्रेया रितेश सोनवानी) द्वारा ÷स्मार्ट और सुरक्षित मल्टीमीडिया ATM÷ ने ?15,000 के साथ साइंस जीनियस पुरस्कार जीता।

सुको के निर्दश पर सारे बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के निर्देश

स्कूलों में बच्चों को आवारा कुत्तों से बचाने के लिए शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था लागू

रायपुर, संवाददाता।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूओ मोटो व्राइट पेटीसन सिविल नंबर 05/2025 में दिए गए स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुपालन में तथा छत्तीसगढ़ शासन, पशुधन विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के पत्र क्रमांक E-166671 & 153108/-42/1802/2025 /1724 दिनांक 13.11.2025 के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया गया है।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब राज्य के प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य या संस्था प्रमुख को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। नोडल अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि स्कूल परिसर या आसपास यदि आवारा कुत्ते दिखाई दें, तो उसकी जानकारी तुरंत संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निगम के डॉग क्रैचर नोडल अधिकारी को दें। साथ ही स्कूल परिसर में कुत्तों का प्रवेश रोकने के लिए आवश्यक अवरोधक उपाय सुनिश्चित करें। यदि किसी बच्चे के साथ आवारा कुत्ते द्वारा काटे जाने की घटना होती है, तो बच्चे को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी, ताकि आवश्यक प्राथमिक इलाज समय पर उपलब्ध कराया जा सके।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का उद्देश्य प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित, भय-मुक्त और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप तथा पशुधन विकास विभाग के मार्गदर्शन में यह अभियान पूरे प्रदेश में तेजी और संवेदनशीलता के साथ लागू किया जा रहा है।

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

संपादकीय

दक्षिण अफ्रिका में भारत के लीडरशीप का दिखा जोहर

भारत में आर्थिक गैर-बराबरी अत्यधिक बढ़ चुकी है, यह कोई नया तथ्य नहीं है। नई बात सिर्फ यह है कि इस बार जी-20 समूह की तरफ से नियुक्त मशहूर अर्थशास्त्रियों के टास्क फोर्स ने इस ओर ध्यान खींचा है। जोसेफ स्टिग्लिट की अध्यक्षता वाले इस टास्क फोर्स ने गैर-बराबरी बढ़ने के परिणामों का भी उल्लेख किया है। साथ ही बताया है कि इस पर किस तरह लगाम लगाया जा सकता है। फिलहाल, जी-20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है। वहां के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की पहल पर ये टास्क फोर्स बना। उसने बताया है कि इस समस्या को नजरअंदाज करना कितना हानिकारक है। टास्क फोर्स के मुताबिक अत्यधिक आर्थिक विषमता से राजनीति पटरी से उतर जाती है, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है।

संविधान : लोकतंत्र की आत्मा और सुशासन का आधार

ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

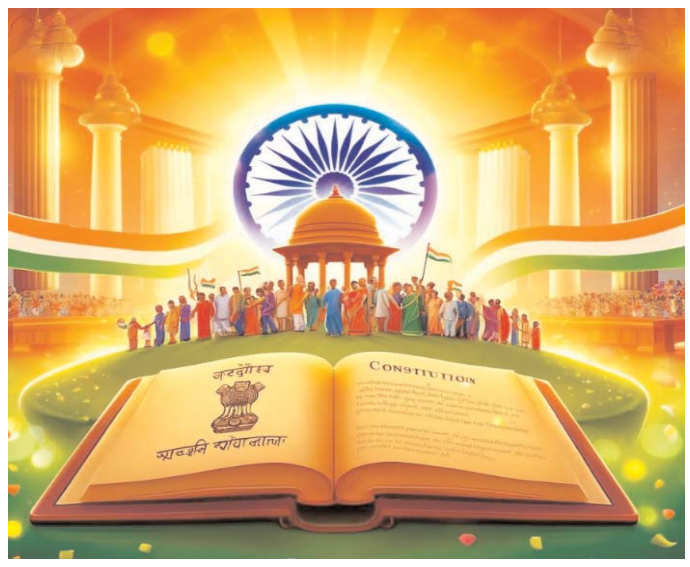

संविधान किसी भी राष्ट्र का चरित्र, मर्यादा और दिशा निर्धारित करता है। यह केवल विधिक दस्तावेज नहीं होता, बल्कि एक जीवंत मूल्य-व्यवस्था होती है जो राष्ट्र की आत्मा को परिभाषित करती है। संविधान दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र की स्थिरता, एकता और प्रगति का आधार हमारे संविधान की दूरदर्शिता, उदारता और संतुलन है। इसलिए किसी भी राष्ट्र में सुशासन की पहली और अनिवार्य शर्त यही है कि संविधान सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहे, केवल शासन के लिए ही नहीं, बल्कि नागरिक जीवन के हर व्यवहार, आचरण और विचार में भी।

भारत गणराज्य का संविधान 26 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ? भीमराव आंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवम्बर 2015 से भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस सम्पूर्ण भारत में हर वर्ष मनाया जा रहा है। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवम्बर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया और 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया।

भारत का संविधान दुनिया के सबसे विस्तृत एवं आधुनिक संविधानों में माना जाता है। यह हमें केवल अधिकार ही नहीं देता, बल्कि कर्तव्यों की भावना भी जगाता है। यह हमें समानता, न्याय और स्वतंत्रता से सज्जित करता है, साथ ही यह भी बताता है कि इन आदर्शों को जीवित रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। जब किसी राष्ट्र में संविधान की अवहेलना शुरू होती है, तब लोकतंत्र डगमगाने लगता है। इसलिए संविधान का सम्मान करना एक विधिक प्रक्रिया का पालन मात्र नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चरित्र की बुनियाद है। आज संविधान दिवस पर यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि संविधान की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही दृढ़ता से बनी हुई है या नहीं? उत्तर स्पष्ट है-हाँ, क्योंकि हमारा समाज परिवर्तनशील है, चुनौतियाँ बदलती हैं, लेकिन न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल आदर्श समय से परे हैं। संविधान की उपयोगिता तभी सिद्ध होती है जब शासनकर्ता उसे सर्वोपरि मानें और नागरिक उसे जीवन का नैतिक मार्गदर्शक बनाएं।

इसी संदर्भ में यह भी विचारणीय है कि संविधान को केवल हाथ में लेकर जगह-जगह प्रदर्शन करना, जैसाकि कुछ राजनीतिक नेता, विशेषकर राहुल गांधी, करते हैं, क्या सचमुच संविधान के सम्मान का प्रतीक है? संविधान की प्रति का सार्वजनिक प्रदर्शन तब सार्थक होता है जब उसके मूल्यों को जीवन में उतारा जाए, उसके अनुच्छेदों का पालन किया जाए, उसके प्रति संयम, गरिमा और श्रद्धा रखी जाए। संविधान को राजनीतिक हथियार बनाकर भीड़ भावनाओं को उकसाने का प्रयास, संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। संविधान को मंचों पर लहराना सम्मान नहीं, बल्कि उसकी गंभीरता का अवमूल्यन है। संविधान कोई राजनीतिक पोस्टर या प्रदर्शन की वस्तु नहीं, वह राष्ट्र की मर्यादा का दस्तावेज है, जिसे विवेक, संयम और ईमानदारी से समझने एवं पालन करने की आवश्यकता होती है।

संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण भी यही रहा कि संविधान तभी सफल होगा जब उसके अनुयायी चरित्रवान, प्रतिबद्ध और राष्ट्रहित साधक हों। बाबा साहेब ने कहा था-÷संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह खराब सिद्ध होगा।÷ उनका यह चिंतन आज सबसे अधिक प्रासंगिक है। उन्होंने संविधान को बनाया, पर उससे भी अधिक उन्होंने एक नैतिक चेतना जागृत की कि संविधान की शक्ति उसके लेखों में नहीं, बल्कि उस नागरिक चेतना में है जो उसे पालन करने के लिए तैयार रहती है। अंबेडकर का यह भी आग्रह था कि संविधान को केवल राजनीतिक बहस का साधन न बनाया जाए, बल्कि समाज सुधार और मनुष्य निर्माण की दिशा में उसका प्रयोग हो। उनके अनुसार संविधान को समझना यानी भारतीय समाज की आत्मा को समझना।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संविधान को सर्वोच्च सम्मान देते हुए उसे शासन का आधारस्तंभ बनाया है। वे बार-बार कहते रहे हैं कि ÷संविधान हमारी शासन-व्यवस्था का पवित्र ग्रंथ है।÷ उनकी दृष्टि में संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं बल्कि अच्छे शासन, सामाजिक विश्वास और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। संसद के आरंभिक सत्र हों, प्रमुख राष्ट्रीय अवसर हों या आम जनता से संवाद, हर बार उन्होंने संविधान को सर्वोच्च स्थान दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि ÷संविधान का पालन करना केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति का सर्वोच्च रूप है।÷ उनकी सरकार की प्राथमिकता यही रही है कि प्रत्येक नीति, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक योजना संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो। मोदी के नेतृत्व में कई ऐसे प्रयास हुए जिनका उद्देश्य संविधान के प्रति जन-जागरण बढ़ाना था, जैसे 'संविधान के प्रति कर्तव्य पालन' अभियान, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करना, पारदर्शी शासन एवं नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। उन्होंने संविधान दिवस को केवल समारोह न बनाकर राष्ट्रीय आत्मचिंतन का पर्व बनाने का प्रयास किया, जिससे हर नागरिक संविधान को केवल पढ़े नहीं बल्कि महसूस करे, समझे और जिए।

संविधान का सम्मान केवल शासन की जिम्मेदारी भर नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। यदि नागरिक संविधान को केवल विद्यालयों की पाठ्यपुस्तकों में सीमित मानते रहेंगे, तो यह राष्ट्र अपने लोकतांत्रिक आदर्शों से दूर होता जाएगा। संविधान का वास्तविक सम्मान तब है जब हम अपने दैनिक जीवन में समानता का पालन करें, न्याय को महत्व दें, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि रखें, किसी के साथ भेदभाव न करें, हिंसा या अराजकता के बजाय संवाद एवं शांति का मार्ग चुनें। आज जब दुनिया में असहिष्णुता, चरमपंथ और राजनीतिक कटुता बढ़ रही है, तब हमारा संविधान एक शीतल छाया की तरह हमें संरक्षण देता है। यह हमें बताता है कि राष्ट्र केवल सत्ता परिवर्तन का खेल नहीं बल्कि मूल्यों की निरंतरता है। संविधान इन्हीं मूल्यों को स्थिर रखता है।

संविधान दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि संविधान का सम्मान केवल राष्ट्रीय पर्वों पर नहीं बल्कि प्रतिदिन के जीवन में होना चाहिए। नागरिकों के मन में संविधान के प्रति आदर की आदत विकसित हो, यह तभी संभव है जब समाज में संवैधानिक शिक्षण को मजबूत किया जाए, देश के नागरिकों को अधिकारों के साथ कर्तव्यों का बोध कराया जाए और हर स्तर पर संवैधानिक आचरण को प्रोत्साहित किया जाए। आज आवश्यकता है कि संविधान को राजनीतिक विवादों से ऊपर उठाया जाए। उसे नारा, प्रदर्शन और विरोध की वस्तु न बनाया जाए। बल्कि उसे एक ऐसे प्रकाश स्तंभ के रूप में देखा जाए जो हमें न्यायपूर्ण, समतामूलक और शांतिपूर्ण समाज की ओर ले जाता है। यदि हम संविधान का सम्मान करेंगे तो राष्ट्र मजबूत होगा; यदि हम इसकी अवमानना करेंगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा।

संविधान दिवस केवल इतिहास का स्मरण नहीं है, यह भविष्य की जिम्मेदारी का बोध भी है। इसे मनाते हुए हमें अपनी राष्ट्रीय प्रतिज्ञा दोहरानी चाहिए कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, उसके मूल्यों को जीवन में उतारेंगे और अपने देश को ऐसा बनाएंगे जैसा हमारे संविधान ने परिकल्पित किया है, न्यायपूर्ण, समानतामूलक, स्वतंत्र और बंधुत्वपूर्ण। इसी में भारत का भविष्य है, इसी में हमारी लोकतांत्रिक शक्ति का चरम है, और इसी में एक प्रगतिशील राष्ट्र की आत्मा बसती है

यह निजी विचार है।

लालू प्रसाद यादव के राजद को बिहार ने नकार दिया। अब परिवार में द्वंद्।

अजय दीक्षित

बिहार विधानसभा चुनावों में राजद की करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव परिवार में घनघोर द्वंद्व मच गया है। लालू प्रसाद यादव को एक किडनी देने वाली उनकी पुत्री रोहणी आचार्य ने रात्रि में घर छोड़ दिया। बताया जाता है कि उसे चुनाव परिणाम आने के बाद चप्पल से पीटा गया है। ऐसा रोहणी आचार्य ने खुद हवाई अड्डे पर मीडिया को बताया।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल वाटर लू का युद्ध साबित होगा।अब यहां यह पार्टी खत्म होती जाएगी ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ का मानना है।इन चुनावों में राजद माई फैक्टर भी खत्म हो गया है।1989 राजीव गांधी की हार के बाद केंद्र में जनता दल की सरकार बनी और जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की मदद से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने।1989 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव ने शासन किया। इन दौरान बिहार में जैसे गुंडा राज हो गया। सरकारी ठेका, शराब ठेके, जमीनों पर कब्जा, शासकीय योजनाओं की लूट खसोट खूब हुई । असामाजिक तत्वों ने राजद के झंडे तले खूब धन कमाया भी और उगाया भी।इन दौरान शासकीय बजट को बिना काम किए लालू प्रसाद यादव के समर्थकों ने जमकर दोहन किया। केंद्र पोषित शासकीय योजनाओं का पैसा हड़पना शुरू कर दिया तो योजनाएं ठप्प हो गई।

1998 में भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व वाली सरकार बनी यही से उल्टी गिनती शुरू हो गई।

दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव ने जंगलराज कायम कर दिया।पूरा बिहार जलने लगा और तो और लालू प्रसाद यादव सवर्ण, पिछड़ी जातियों को प्रताड़ित करने लगे वे इसे सामाजिक न्याय कहते थे।एक अपहरण उद्योग भी बन गया। मुज़्ज़रपुर के गोलू नामक बालक के अपहरण हत्या से पूरे बिहार में सन्नाटा छा गया था लेकिन लालू प्रसाद यादव को कोई चिंता नहीं थी ।उनकी पुत्री मिसा भारती की शादी में पटना में साधु यादव के गुंडों ने इतना धमाल मचाया कि कारों के शो रूम से कार उठा ले गए, सोफा सेट ,अन्य सामान उठा ले गए।

नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता दल बनाया। उधर लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल गए तो उनकी बिना पढ़ी लिखी पत्नी रावड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी और जेल से ही सरकार चलने लगी ।तब बिहार बासी समझे कि उनके साथ धोखा हो रहा है।2005 में एनडीए की सरकार बनी जो आज तक चल रही है।2025 विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने राजद को हरा दिया। लालू प्रसाद यादव ने जब रेल मंत्री थे तब जमीन के बदले नौकरी दी ।जमीन घूस के रूप में दी गई थी और उसकी जांच ईडी, सीबीआई कर रही है।

बिहार की जनता इतना जंगल राज झेलने के बाद अब राजद, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती,को कभी भी पसंद नहीं करेगी ।यद्यपि यादव, मुस्लिम वोट पर राजद की पकड़ बरकरार है। लेकिन जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा,हम,इल्म ,पार्टियों गठजोड़ 49 फीसदी वोट हासिल कर राजद, कांग्रेस, महागठबंधन को चारों खाने चित्त कर देता है।

यह निजी विचार है।

भारत की श्रम संहिताएं और महिला श्रमिक : अपेक्षाकृत अधिक समावेशी और लैंगिक रूप से संवेदनशील अर्थव्यवस्था की ओर

श्रीमती उमा मेय्यप्पन

वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता के बीच, भारत की नई श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन घरेलू लचीलेपन को मजबूत करने और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मौका है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना न केवल मैन्यूफैक्चरिंग या तकनीकी क्षमता का विस्तार, बल्कि समावेशी एवं सुदृढ़ संस्थानों के निर्माण पर भी निर्भर करेगा। सच्ची आत्मनिर्भरता एक ऐसी अर्थव्यवस्था के निर्माण में निहित है जहां प्रत्येक नागरिक, विशेषकर महिलाएं, देश की विकास गाथा में सार्थक रूप से भाग ले सकें। भारत ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2023-24 के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं का श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 22.0 प्रतिशत से बढ़कर 40.3 प्रतिशत हो गया है। जबकि, इसी अवधि में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 41.7 प्रतिशत हो गई है। ये आंकड़े श्रम बाजार में भागीदारी के मामले में व्याप्त लैंगिक अंतर में आई उल्लेखनीय कमी को दर्शाते हैं तथा व्यापक आर्थिक समावेशन की दिशा में सकारात्मक बदलाव की ओर भी इशारा करते हैं। फिर भी, महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा श्रमबल से बाहर है और जो महिलाएं कार्यरत हैं भी, उनमें से कई उन अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं जहां उन्हें कम वेतन, नौकरी की सीमित सुरक्षा और न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा की समस्या से जूझना पड़ रहा है। कृषि एवं घरेलू काम से लेकर घर-आधारित उद्यमों और गिग प्लेटफॉर्म तक, अनौपचारिक रोजगार अक्सर नाजुक आर्थिक स्थिति और असमानता को मजबूत करता है।

इस संदर्भ में, भारत के श्रम कानूनों को हाल ही में चार व्यापक संहिताओं में संहिताबद्ध किया जाना इन कमियों को दूर करने का एक अनूठा मौका है। औपचारिकीकरण, संरक्षण और समान पहुंच पर ध्यान केन्द्रित करके, इन सुधारों का उद्देश्य अपेक्षाकृत अधिक समावेशी और सुदृढ़ श्रम बाजार की नींव रखना है। इस प्रयास में भारत अकेला नहीं है। वियतनाम, इंडोनेशिया, मिस्र और मैक्सिको सहित कई विकासशील देशों ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इनमें मातृत्व संबंधी लाभ का विस्तार करना तथा स्वैच्छिक सहमति, सुरक्षित परिवहन, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, महिला पर्यवेक्षण एवं उत्पीड़न-विरोधी ठोस सुरक्षा जैसे सुरक्षात्मक उपायों के तहत महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देना शामिल है। ऐसे उपाय सिर्फ रोजगार को ही संभव बनाने से जुड़े नहीं हैं, बल्कि इनका जुड़ाव महिलाओं की गरिमा, स्वायत्तता और आर्थिक प्रगति में समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने से भी है।

अब जबकि भारत आत्मनिर्भरता और सतत विकास की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखे हुए है, एक सच्ची समावेशी एवं न्यायसंगत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए महिलाओं को नीति और श्रम सुधार के केन्द्र में रखना अहम होगा। इन संहिताओं में निहित अनेक प्रावधानों में से कई, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी एवं सशक्तिकरण की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। इन सुधारों का उद्देश्य कार्यस्थलों को अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित, अधिक लचीला और अधिक न्यायसंगत बनाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं पुरुषों के साथ समान स्तर पर अर्थव्यवस्था में भाग लें और उसका लाभ उठा सकें। वेतन और कामकाज की स्थितियों में लिंग-आधारित भेदभाव की समाप्ति - भारत के श्रम सुधार, विशेष रूप से वेतन संहिता (2019) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 का उद्देश्य वेतन तथा कामकाज की स्थितियों में लंबे समय से चले आ रहे और श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को सीधे प्रभावित करने वाले लिंग-आधारित भेदभाव से निपटना है।

वेतन संहिता (2019) भर्ती और वेतन में लिंग-आधारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करके ÷समान कार्य के लिए समान वेतन÷ के सिद्धांत को सुदृढ़ करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संहिता संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन कवरेज को सार्वभौमिक बनाती है। यह प्रावधान कम वेतन वाले अनौपचारिक पेशों में कार्यरत महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें एक बुनियादी स्तर की आय संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, एक राष्ट्रीय फ्लोर वेज ढांचे की शुरुआत उचित वेतन के लिए मोल-भाव करने की महिला श्रमिकों की क्षमता को मजबूत करती है और साथ ही वेतन के स्तरों में क्षेत्रीय असमानताओं को भी कम करती है। यह लैंगिक आधार पर वेतन में व्यापक अंतर को दूर करने और सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आय संबंधी सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके समानांतर, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 महिलाओं को पारंपरिक रूप से नियत कामकाज के घंटों से परे काम करने की अनुमति देकर उनकी आर्थिक भागीदारी के नए अवसर खोलती है। पूर्व में 1948 के फैक्ट्री अधिनियम के तहत कारखानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रात्रि पाली में महिलाओं को काम करने से रोकने संबंधी प्रतिबंध के उलट, इस नए संहिता का उद्देश्य कमाई की क्षमता के संदर्भ में पुरुषों और महिलाओं के बीच समान अवसर प्रदान करना है। इस प्रतिबंध के हटने से महिलाएं पारंपरिक रूप से पुरुषों के प्रभुत्व वाली पाली में काम कर सकेंगी। इससे अपने पुरुष समकक्षों के बराबर वेतन अर्जित करने की उनकी क्षमता बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों ने पहले ही रात्रि पाली में महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध को हटा लिया है। इसके परिणामस्वरूप पुरुषों के रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव डाले बिना महिलाओं के रोजगार में वृद्धि हुई है, खासकर बड़ी व निर्यात-उन्मुख फर्मों में। इससे पता चलता है कि महिलाओं को रात्रि पाली में शामिल करने से औपचारिक क्षेत्र के रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

हालांकि रात में काम करना अनूठी, खासकर सुरक्षा से जुड़ी, चुनौतियां पेश करता है। इसे स्वीकार करते हुए, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहितायह सुनिश्चित करती है कि महिलाओं को केवल उनकी स्पष्ट सहमति से ही रात्रि पाली में नियुक्त किया जाए और सुरक्षा के पर्याप्त उपाय लागू हों। नियोक्ताओं द्वारा सुरक्षित परिवहन, अलग शौचालय और यौन उत्पीड़न रोकने के उपायों सहित सुरक्षा संबंधी अन्य व्यवस्थाएं प्रदान करना आवश्यक है। यह बदलाव उस पारंपरिक, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण से दूर हटने का प्रतीक है जो सुरक्षा के नाम पर महिलाओं के काम के घंटों को सीमित करता था। इसके बजाय, यह कदम महिलाओं को उनकी सुरक्षा एवं सम्मान को प्राथमिकता देने वाले ढांचे के भीतर विकल्प और स्वायत्तता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है।

महिलाओं की देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना और व्यावसायिक सुरक्षा, एवं स्वास्थ्य को बेहतर बनाना

श्रम बाजार में महिलाओं की कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाला एक अन्य प्रमुख कारक उन पर काम का दोहरा बोझ है। इस बोझ के तहत उन्हें वेतनभोगी काम के साथ-साथ घरेलू एवं बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बिठाना पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमानों के अनुसार, 2023 में, 74.8 करोड़ लोग (15 वर्ष या उससे अधिक आयु के) देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के कारण वैश्विक श्रमबल का हिस्सा बनने में असमर्थ थे। इनमें अधिकांश महिलाएं थीं। इसके अलावा, महिलाओं के अनुकूल एक ऐसे बुनियादी ढांचे की जरूरत है जो कार्यस्थल पर लैंगिक दृष्टि से महिलाओं और पुरुषों की भिन्न भिन्न प्रकार की विशेष जरूरतों को पूरा कर सके।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, शौचालय और शिशुगृह संबंधी सुविधाओं के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करती है। यह प्रावधान लंबे समय से चली आ रही बुनियादी ढांचे की उन कमियों को दूर करता है, जिसने महिलाओं को विशेष रूप से मैन्यूफैक्चरिंग, खनन और निर्माण क्षेत्रों में रोजगार पाने से रोका है। खासतौर पर 50 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य शिशुगृह सुविधाओं का प्रावधान भले ही नया नहीं है, लेकिन यह संहिताकरण के जरिए कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। यह कामकाजी माताओं का समर्थन करने और साझा देखभाल जिम्मेदारियों को आम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन प्रावधानों के पूरक के रूप में, औद्योगिक संबंध संहिता (2020) के तहत जारी सेवा क्षेत्र के लिए मॉडल स्थायी आदेश, अब नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच आपसी समझौते के आधार पर घर से काम करने की व्यवस्था की अनुमति देते हैं। यह एक हद तक लचीलापन लाता है जो विशेष रूप से सेवा और ज्ञान-आधारित पेशों में महिलाओं को भुगतान किए गए काम और देखभाल की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बिठाने में और अधिक सहायता कर सकता है।

इसके अलावा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच को भी अनिवार्य बनाती है और ठेका कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुविधाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ताओं पर डालती है। ये उपाय उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जो आउटसोर्स या आकस्मिक पदों पर कार्यरत हैं जहां पेशेगत स्वास्थ्य एवं कल्याण की उपेक्षा की जाती है। इसी प्रकार सुरक्षित परिवहन, अच्छी रोशनी वाले कामकाज के वातावरण और स्वास्थ्यकर सुविधाएं प्रदान करने पर जोर देने से रात्रि पाली या दूर-दराज स्थित कार्यस्थलों पर काम करने की महिलाओं की इच्छा और क्षमता बेहतर हो सकती है। व्यक्तिगत रूप से इन जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई महसूस करने वाले छोटे उद्यम आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने हेतु सामूहिक रूप से सहयोग और संसाधन जुटा सकते हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न महिलाओं का ध्यान रखना और सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना

लेकिन भारत के श्रम सुधारों की आधारशिला सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) है, जो खासतौर पर तेजी से बढ़ते गिग और अनौपचारिक क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है। यह मुख्य रूप से औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों पर केन्द्रित और देश के अधिकांश श्रमबल, विशेषकर अनौपचारिक, आकस्मिक या स्व-नियोजित भूमिकाओं में कार्यरत महिलाओं की अनदेखी करने वाले पूर्व के श्रम कानूनों की तुलना में एक बड़ा बदलाव है। पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार, गैर-कृषि क्षेत्र में कार्यरत 61 प्रतिशत महिला श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों में संलग्न हैं।

कई महिलाएं कामकाज के लचीले घंटों की वजह से असंगठित क्षेत्र की ओर रुख करती हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां वेतनभोगी काम और देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना संभव होता है। परिणामस्वरूप महिलाएं कृषि, घरेलू एवं देखभाल संबंधी काम और सूक्ष्म या घर-आधारित उद्यम जैसे अनौपचारिक क्षेत्र में अत्यधिक केन्द्रित हैं, जहां सामाजिक सुरक्षा सीमित रूप से सुलभ है। इसके अलावा, महिलाएं तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से घरेलू, देखभाल एवं सौंदर्य सेवाओं में बड़ी संख्या में प्रवेश कर रही हैं, जहां ऐसे लाभ अभी भी दुर्लभ ही हैं।

सामाजिक सुरक्षा, जरूरी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके महिलाओं के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अनियमित रोजगार या बेरोजगारी के दौरान लगने वाले वित्तीय झटकों की वजह से महिलाओं की नाजुक स्थिति में कमी लाती है। उदाहरण के लिए, मातृत्व अवकाश और स्वास्थ्य बीमा यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएं वित्तीय अस्थिरता का जोखिम उठाए बिना अपनी और अपने परिवार की देखभाल कर सकें। पेंशन दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करती है और यह उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिन्हें अक्सर असमान वेतन, करियर ब्रेक और देखभाल करने वाली भूमिकाओं के कारण जीवन भर कम आय की स्थिति से गुजरना पड़ता है।

इन चुनौतियों के जवाब में, सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) असंगठित, गृह-आधारित, स्व-नियोजित, गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की पहचान और पंजीकरण की शुरुआत करती है। इन समूहों को शामिल करने के उद्देश्य से ÷श्रमिक÷ की परिभाषा का विस्तार करके, यह संहिता देश में रोजगार की विकसित प्रकृति को स्वीकार करती है और सामाजिक सुरक्षा में लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर करने का लक्ष्य रखती है। इसके अलावा, यह संहिता मातृत्व लाभ अधिनियम (1961) को अपने ढांचे में समन्वित करती है और ÷परिवार÷ की परिभाषा का विस्तार करते हुए आश्रित ससुराल वालों को शामिल करती है, जिससे कई महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली देखभाल की व्यापक जिम्मेदारियों को मान्यता मिलती है। इन प्रावधानों को लागू करते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित और प्रवासी श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं, जो ऐसे श्रमिकों की दृश्यता बढ़ाएगा और अनौपचारिक क्षेत्र में महिला श्रमिकों को अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगा।

हालांकि, इस संहिता के तहत प्रस्तावित सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल करना है। पहले स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में वर्गीकृत, ये श्रमिक अधिकांश श्रम सुरक्षा के दायरे से बाहर थे। यह संहिता अब उनके आर्थिक योगदान को मान्यता देती है और उनके लिए समर्पित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के निर्माण को अनिवार्य बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह कि यह संहिता साझा योगदान का एक ऐसा मॉडल पेश करती है, जिसमें न केवल श्रमिकों, बल्कि उन्हें नियुक्त करने वाले प्लेटफ़ॉर्म या एग्रीगेटर्स को भी इन योजनाओं में योगदान करना आवश्यक है।

यह निजी विचार है।

केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने नेत्रहीन भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सम्मानित किया;

पीआईबी

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आज नेत्रहीन भारतीय महिला क्रिकेट टीम को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया, जिन्होंने नवंबर 2025 में आयोजित पहले टी20 विश्व कप में जीत हासिल की। केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनकी ऐतिहासिक जीत तथा प्रेरणादायक यात्राओं के लिए उन्हें बधाई दी। पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और नेत्रहीनों के लिए एसबीआई प्रथम महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट की विश्व आयोजन समिति की अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी लेखी भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं।

कप्तान दीपिका टी. सी., कर्नाटक से और उप-कप्तान गंगा एस. कदम,महाराष्ट्र से, के नेतृत्व में नेत्रहीन भारतीय महिला क्रिकेट टीम पूरे टूर्नामेंट में अपराजेय रही, जिसने उल्लेखनीय टीम वर्क, जुझारूपन और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया।

कोलंबो में 23 नवंबर 2025 (रविवार) को नेपाल के खिलाफ एक ऊर्जा से भरपूर फाइनल मुकाबले में, भारत ने सात विकेट से जीत हासिल की। भारत ने नेपाल को 114/5 तक सीमित कर दिया और केवल 12.1 ओवर में लक्ष्य का पीछा कर लिया। यह जीत पूरे टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन से संभव हो पाई।

फूला सरेन ने निर्णायक 27 गेंदों पर 44 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। कप्तान दीपिका टी. सी. ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 58 गेंदों पर यादगार 91 रनों सहित अपने ऑलराउंडर शानदार प्रदर्शन के लिए वाहवाही बटोरी।

विशाखापत्तनम की 10वीं कक्षा की छात्रा करुणा पांगी कुमारी ने फाइनल में अपने संयमित 42 रनों से प्रभावित किया। 2003 में जन्मी दुर्गा येवले ने कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से एक छोटे शहर की पृष्ठभूमि से राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने की अपनी यात्रा से कई लोगों को प्रेरित किया।

टीम को संबोधित करते हुए, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि उनकी उपलब्धि ÷बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना को दर्शाती है और एक ऐसे राष्ट्र की आकांक्षाओं को दर्शाती है जो हर लड़की को सपने देखने, आकांक्षा रखने और हासिल करने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।÷ उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसी उपलब्धियाँ विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति को आगे बढ़ाने में भारत की बेटियों की क्षमता को प्रदर्शित करती हैं, जहाँ सुलभ और समावेशी अवसर हैं।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के लिए बाधाओं को तोड़ने और नए मानक स्थापित करने के लिए टीम की प्रशंसा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह जीत दृढ़ संकल्प, प्रतिभा और राष्ट्रीय गौरव का एक शक्तिशाली उदाहरण है।

मंत्रालय ने टीम की मेज़बानी करने और उनकी ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाने पर गहरा गर्व व्यक्त किया, यह देखते हुए कि उनकी उपलब्धि न केवल महिला नेत्रहीन क्रिकेट में, बल्कि लैंगिक समानता और समावेशी विकास की भारत की व्यापक यात्रा में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

(मनेंद्रगढ़) एसआईआर समीक्षा के लिये मनेन्द्रगढ़ पहुँचीं कांग्रेस सह-प्रभारी जरिता लेतफलांग

जनप्रतिनिधियों और बीएलए से ली जमीनी फीडबैक

कार्यकर्ताओं को दिये गये आवश्यक दिशानिर्देश

मनेन्द्रगढ़, प्रदेशभर में चल रहे एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू) अभियान की समीक्षा को लेकर सोमवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सह-प्रभारी जरिता लेतफ्लांग मनेन्द्रगढ़ पहुँचीं। उनके आगमन पर जिले के कांग्रेसजनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया जिसके बाद उन्होंने संगठन से जुड़े जनप्रतिनिधियों, बीएलए, ब्लॉक पदाधिकारियों और बूथ प्रभारियों के साथ विस्तृत बैठक की।

बैठक में एसआईआर प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति, बूथ स्तर पर हो रहे कार्य, मतदाता सूची संशोधन की प्रगति और फ ील्ड में आ रही समस्याओं पर गहन चर्चा हुई। बीएलए और कार्यकर्ताओं ने मतदाता सत्यापन से जुड़े तकनीकी मुद्दों, फॉर्म त्रुटियों, दस्तावेज़ उपलब्धता और फ ील्ड विज़िट के दौरान आने वाली चुनौतियों की जानकारी सह-प्रभारी को दी।

यूपीएससी से उभरने वाला नेतृत्व 2047 में विकसित भारत को आकार देगा : डॉ. जितेंद्र

यूपीएससी ने निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा में वैश्विक मानक स्थापित किए हैः लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

पीआईबी

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित यूपीएससी के शताब्दी समारोह 'शताब्दी सम्मेलन' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को ÷भारत के शासन के इस्पात ढांचे का संरक्षक÷ बताया। मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और यूपीएससी अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार की उपस्थिति में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी भारत के स्वतंत्रता-पूर्व और स्वतंत्रता-पश्चात के युगों में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और पारदर्शिता के एक स्तंभ के रूप में खड़ा रहा है और राष्ट्र की लोकतांत्रिक यात्रा का मूक साक्षी रहा है। उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा सिविल सेवा को ÷भारत का इस्पात ढाँचा÷ बताए जाने का स्मरण करते हुए कहा, *÷यह संघ लोक सेवा आयोग ही है जिसने इस इस्पात ढाँचे के

संरक्षक होने की जिम्मेदारी निभाई है।÷

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2025 कई ऐतिहासिक पड़ावों का प्रतीक है, जैसे सरदार वल्लभभाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती और वंदे मातरम् की रचना के 150 वर्ष, जो इसे भारत की सांस्कृतिक, संवैधानिक और राष्ट्रवादी विरासत से गहन रूप से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा, ÷इसलिए, यह गर्व की बात है कि यूपीएससी की शताब्दी भी इसी ऐतिहासिक वर्ष में पड़ रही है, जो आयोग की यात्रा को भारत के लोकतंत्र और शासन की व्यापक कहानी से जोड़ती है।÷

यूपीएससी के निरंतर विकास की सराहना करते हुए, डॉ. सिंह ने आयोग की दूरदर्शी सोच को दर्शाते हुए हाल ही में की गई कई पहलों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने यूपीएससी के 'प्रतिभा सेतु' पोर्टल की विशेष रूप से सराहना की, जिसका उद्देश्य उन उम्मीदवारों के लिए नए अवसर पैदा करना है जो सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न चरणों में सफल तो हुए हैं, लेकिन अंतिम चयन तक नहीं पहुँच पाए। इसके लिए उन्हें निजी क्षेत्र और संस्थागत अवसरों से जोड़ना ज़रूरी है। उन्होंने इस कदम को ÷प्रतिभा और अवसर के बीच एक अभिनव सेतु÷ बताया, जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत की बौद्धिक क्षमता नष्ट न हो, बल्कि राष्ट्रीय विकास के लिए उसका लाभ उठाया जाए।

डॉ. सिंह ने भर्ती, सेवा नियमों के निर्माण और अद्यतन करने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समीक्षा और लोक सेवा के लिए नैतिक मानदंड निर्धारित करने से परे यूपीएससी की व्यापक भूमिका पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि संवैधानिक संस्थाओं से जुड़ी उभरती चुनौतियों और बहसों के बावजूद, यूपीएससी ÷भारत के संवैधानिक मूल्यों, योग्यता और निष्पक्षता की सर्वोच्च परंपराओं÷ को कायम रखे हुए है। अपने भाषण के समापन पर, डॉ. सिंह ने कहा, ÷विकसित भारत ञ्च2047 के निर्माता इसी संस्थान से उभरेंगे जिसने भारत के सर्वश्रेष्ठ सिविल सेवकों की कई पीढ़ियों को प्रशिक्षित किया है।÷ संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा 26-27 नवंबर 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा दो दिवसीय 'शताब्दी सम्मेलन' (शताब्दी सम्मेलन), आयोग की राष्ट्र निर्माण की 100 वर्षीय यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस आयोजन में यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों (पीएससी) के वर्तमान और पूर्व अध्यक्षों और सदस्यों के साथ-साथ भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विद्वान और शासन एवं लोक प्रशासन से जुड़ी प्रतिष्ठित हस्तियाँ शामिल होंगी।

स्वागत भाषण देते हुए, यूपीएससी अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया और इस अवसर को ÷यूपीएससी की एक शताब्दी की गौरवशाली यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर÷ बताया। उन्होंने मुख्य भाषण देने के लिए माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला और आयोग को निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग देने के लिए डॉ. जितेंद्र सिंह का आभार व्यक्त किया। यूपीएससी के संवैधानिक दायित्व की पुष्टि करते हुए, डॉ. कुमार ने कहा, इस पावन संविधान दिवस पर, संघ लोक सेवा आयोग अपनी भर्ती, परीक्षा और पदोन्नति प्रणालियों में निष्पक्षता, योग्यता और समता के आदर्शों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नवंबर 2025 ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम संपन्न

16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 80 विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया

पीआईबी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग-एनएचआरसी का 2025-2026 का चौथा ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम संपन्न हो गया है। इसे 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 80 विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक पूरा किया। ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम 10 नवंबर 2025 को आरंभ हुआ था। < style="te&t-alignÑjustify÷> आयोजन के समापन संबोधन में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव श्री भरत लाल ने प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए कहा कि इतने सारे आवेदकों में से चयनित 80 विद्यार्थियों को मानवाधिकार के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों के साथ संवाद के लिए मिले अवसर पर स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से मानवाधिकार दूत बनने और प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान और मूल्यों को आत्मसात कर मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे उठाने के लिए जागरूकता उत्पन्न करने का आह्वान किया। श्री लाल ने प्रशिक्षुओं को स्मरण कराया कि मानवाधिकार को आत्मसात कर दैनिक आचरण में उनका पालन करना होगा। उन्होंने बल देकर कहा कि एक बेहतर मनुष्य ही दूसरों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है और इसका आरंभ एक ऐसे चरित्र निर्माण से होती है जो अपने आस-पास के लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक, सम्मान प्रदर्शित करने वाला और संवेदनशील हो।

श्री लाल ने कहा कि समाज का हर वर्ग अपने बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा कर सम्मानजनक जीवन जी सकता है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर इस बात पर विचार करने का आह्वान किया कि वे मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को और अधिक प्रभावी तरीके से कैसे और कहाँ विस्तारित कर सकते हैं।

इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संयुक्त सचिव श्रीमती सैदिंगपुई छक्छुआक ने इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रस्तुत की। इंटर्नशिप के दौरान 46 सत्रों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षुओं को मानवाधिकार के विभिन्न पहलुओं की गहन जानकारी दी। श्रीमती सैदिंगपुई ने इंटर्नशिप के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणामों की भी घोषणा की।

इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अन्य संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह भी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता सम्मेलन-2025 कल विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा

यह कार्यक्रम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के गैर-संस्थागत पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगा

सम्मेलन में दत्तक ग्रहण संवाद पर विशेष ध्यान दिया जाएगा; सम्मेलन-2025 नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और दत्तक परिवारों को एकजुट करेगा

पीआईबी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के तत्वावधान में केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा), महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता माह के राष्ट्रव्यापी अनुपालन के एक भाग के रूप में कल 27 नवंबर, 2025 को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता सम्मेलन-2025 का आयोजन करेगा। इस वर्ष का सम्मेलन ÷विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग बच्चों) का गैर-संस्थागत पुनर्वास÷ विषय पर केंद्रित है, जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के अनुसार माता-पिता के सहयोग के बिना बच्चों के लिए समावेशी, करुणामय और परिवार-आधारित देखभाल को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस सम्मेलन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री अनिल मलिक, आंध्र प्रदेश महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग की प्रमुख।

एनटीटीएम ने राष्ट्रीय ध्वज और रक्षा-ग्रेड फाइबर का सम्मानजनक पुनर्चक्रण करने के लिए भारत का पहला वैज्ञानिक मॉडल पेश किया

पीआईबी

कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) ने एक परिवर्तनकारी परियोजना का समर्थन किया है जो तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में स्थिरता को नया स्वरुप प्रदान करता है। इस परियोजना के परिणामस्वरुप आईआईटी दिल्ली के अंतर्गत पानीपत में अटल वस्त्र पुनर्चक्रण एवं स्थायित्व केंद्र की स्थापना हुई, जिसने दो अग्रणी पहलों, राष्ट्रीय ध्वज पुनर्चक्रण पहल और अरामिड फाइबर पुनर्चक्रण कार्यक्रम, के माध्यम से प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं राष्ट्रीय उद्देश्य को एकीकृत किया है। पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) इन नवाचारों और वास्तविक दुनिया पर उनके प्रभावों को प्रदर्शित करने के लिए 28 नवंबर 2025 को पानीपत में एक समर्पित प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम परियोजना के अंतर्गत विकसित तकनीकों पर प्रकाश डालेगा, उद्योग एवं सरकार के हितधारकों को एक मंच पर लाएगा तथा तकनीकी वस्त्रों में नवाचार, स्थिरता और औद्योगिक एकीकरण को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की भूमिका को मजबूत करेगा।

भारत में पहली बार, सेवानिवृत्त राष्ट्रीय ध्वजों का गरिमापूर्ण पुनर्चक्रण करने के लिए एक संरचित एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू की गई है। उद्योग साझेदार द्वारा लागू की गयी यह परियोजना सुनिश्चित करती है कि तिरंगे के कपड़े और संरचनात्मक अखंडता सुरक्षित रहें या बिना गरिमा को नुकसान पहुंचाए इनका जिम्मेदारीपूर्वक पुनः उपयोग हो। यह मॉडल दर्शाता है कि स्थिरता को राष्ट्रभक्ति मूल्यों के साथ किस प्रकार के जोड़ा जा सकता है और यह हर घर तिरंगा अभियान की भावना के साथ दृढ़ता से मेल खाता है।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, बस्तर मण्डल, जगदलपुर

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना

https://eproc.cgstate.gov.in

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है :-
निविदा डाऊनलोड करने की अंतिम तिथि :- 04/12/2025

स.क्र.	नि.आ.सू.क्र./ नि.आ.सू. दिनांक	सिस्टम निविदा क्रमांक निविदा का क्रम	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रूपये लाख में)
01	02	03	04	05
4	197/2025-26 दिनांक 18/11/2025	179917 (प्रथम आमंत्रण)	दन्तेवाड़ा में फायर स्टेशन भवन का निर्माण कार्य, जलप्रदाय, सेनेटरी फिटिंग एवं विद्युतिकरण सहित कार्य।	113.05

निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया एवं निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग के उपरोक्त वेबसाईट में देखे जा सकते है।

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग
बस्तर मंडल जगदलपुर

G-252605031/5

लोकशक्ति
www.lokshakti.in

जिला पंचायत सीईओ ने ली पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक

निर्माण कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी कार्यों को गुणवत्ता व समय-सीमा के भीतर करें पूरा - सीईओ श्री गोकुल रावटे

मनरेगा एवं पीएम आवास कार्यों की करें सतत मॉनिटरिंग

जांजगीर-चांपा / जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे ने जिला पंचायत के सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कार्यों को गुणवत्ता तथा समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए। जिला पंचायत सीईओ ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 15वें वित्त आयोग, जिला एवं जनपद पंचायत विकास निधि, मुख्यमंत्री आंतरिक विद्युतीकरण योजना, डीपीआरसी प्रशिक्षण सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे ने अधिकारियों को निर्देशित किया सभी कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्तापूर्ण निर्माण और जन-सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन तेजी से हो तथा मैदानी अमला नियमित रूप से गांवों का भ्रमण कर कार्य स्थल का निरीक्षण करे। बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) वर्ष 2025-26 के अंतर्गत स्वीकृत नए आवासों की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित कर दी गई। बैठक में सीईओ ने निर्देश दिए कि बिना देरी के आवास निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराएं जाए। सीईओ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन आवासों का निर्माण अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है, उन्हें तत्काल शुरू कराया जाए। इसके लिए मस्टर रोल जारी करने, मैदानी अमले की सक्रियता बढ़ाने तथा विभागों के बीच समन्वय को मजबूत कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि जिले के सभी आवासों को समय सीमा में पूर्ण करें।

जिला पंचायत सीईओ ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत अनुमोदित कार्यों, मजदूरी भुगतान, सामाजिक अंकेक्षण एवं परिसंपत्तियों के संरक्षण की समीक्षा की गई। सीईओ ने लंबित मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान एवं सामग्री भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी न होने देने के निर्देश दिए। सामाजिक अंकेक्षण के लंबित मामलों का त्वरित निराकरण व वसूली सुनिश्चित की जाए, जल संरक्षण, नालों का संरक्षण, खेत-तालाब, वृक्षारोपण एवं एनआरएम के कार्यों को गति दी जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्यों के माध्यम से ग्रामीणों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ और बने हुए परिसंपत्तियों का सतत उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने सभी अधिकारियों को सतत मॉनिटरिंग और समन्वय के साथ योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा कार्यों में पारदर्शिता और जन-सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सभी ग्राम पंचायत भवनों में क्यूआर कोड चस्पा करने, युक्तधारा पोर्टल में लक्ष्य अनुसार कार्य स्वीकृति, साथ ही एनआरएम एवं कृषि श्रेणी के कार्यों में निर्धारित व्यय सुनिश्चित करने, ईएमबी के माध्यम से कार्य मूल्यांकन- सत्यापन समय सीमा में पूर्ण करने और एरिया ऑफिसर एप में आवास एवं मनरेगा कार्यों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी प्रदान किए।

बैठक में अमृत सरोवरों को ग्रामीणों की आजीविका संवर्धन का साधन बनाने पर विशेष जोर दिया गया। सीईओ ने कहा कि अमृत सरोवरों के माध्यम से ग्रामीणों को मत्स्य पालन के लिए प्रेरित किया जाए तथा मत्स्य विभाग के सहयोग से सरोवरों में मत्स्य बीज डाला जाए। बैठक में सीईओ ने कहा कि हितग्राहियों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं सोखता गड्ढा निर्माण के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए।

साथ ही उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभों से भी हितग्राहियों को अवगत कराते हुए अधिकाधिक लोगों को इस योजना का लाभ दिलाने हेतु जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य पूर्ण करने और लाभार्थियों को सशक्त बनाने के लिए प्रशासन द्वारा सतत निगरानी और त्वरित क्रियान्वयन की प्रक्रिया जारी है। बैठक में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ई ई, एसडीईओ, जनपद पंचायत सीईओ, जिला एवं जनपद पंचायत समन्वयक, तकनीकी सहायक, सहायक परियोजना अधिकारी (मनरेगा), कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक सहित मैदानी अमले के अधिकारी मौजूद रहे।

ज्ञानोदय विद्यालय में सागर राठौर सम्मानित किए गए

जांजगीर चांपा /

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित अंतिम परीक्षा परिणाम में ज्ञानोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जांजगीर के पूर्व छात्र सागर राठौर का चयन छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर हुआ है। उनकी यह उपलब्धि विद्यालय एवं क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। सागर राठौर विद्यालय के प्रतिभाशाली और अनुशासित छात्रों में गिने जाते रहे हैं। उन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए थे। उनकी मेहनत, दृढ़ निश्चय और निरंतर अभ्यास ने उन्हें इस सफलता तक पहुँचाया है।

छ ग अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठा पूर्ण पद पर उनके चयन से विद्यालय में खुशियों का माहौल बन गया।

ज्ञानोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं समस्त शिक्षकों द्वारा विद्यालय परिसर में उनका स्वागत किया गया । विद्यार्थियों ने तालियों और फूल-मालाओं,रोली -तिलक से उनका अभिनंदन किया।

इसी दौरान, ज्ञानोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पूर्व छात्र सागर राठौर ने अपनी सफलता के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास को सफलता की कुंजी माना। उन्होंने बताया कि लक्ष्य निर्धारित कर रोजाना योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करने से उन्हें परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुआ।

विद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुरेश यादव ने भी सागर को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि उनके कठिन परिश्रम और निरंतर अध्ययन का परिणाम है। उन्होंने इस सफलता को विद्यालय, शिक्षकों और परिवार के संयुक्त प्रयासों का प्रतिफल बताया।सागर के सम्मान कार्यक्रम में विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती चंचला मिश्रा ने भी उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि सागर की सफलता वर्तमान विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी है। सागर राठौर की इस सफलता ने जांजगीर व आसपास के क्षेत्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति नई ऊर्जा और उत्साह भरा है।

सम्मान समारोह में संजू राठौर सहित शिक्षक – शिक्षिकाएं उपस्थित थे। संचालन एवं आभार प्रदर्शन शिक्षिका मीना यादव द्वारा किया गया

स्कार्पियो और ट्रक मे जबरदस्त भिड़ंत 5 लोगो की दर्दनाक मौत 3 गंभीर रूप से घायल

नवागढ़ में पसरा मातम का माहौल

जांजगीर चांपा /

गत देर रात स्कार्पियो और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत से दर्दनाक हादसा घटित हुआ है जिसमें स्कार्पियो सवार पांच लोगो की मौत होने के साथ तीन गंभीर रूप से घायल अवस्था में है जिन्हे ईलाज के लिए बिलासपुर रिफर किया गया है । मामले में मिली जानकारी अनुसार नवागढ़ निवासी जयराम पिता विमल देवांगन का बारात मंगलवार को पंतोरा गया था जिसमें शामिल होने के लिए नवागढ़ के ही युवक स्कार्पियो क्रमांक cg 11bs 3974 में सवार होकर गए थे , वहां से देर रात वे सभी वापस आ रहे थे तभी रात्री 12.30 बजे हाइवे सड़क मे सुकली गांव के पास स्कार्पियो की ट्रक क्रमांक OD 23P6037 से जबरदस्त भिड़ंत हो गई ।

इस टक्कर में स्कार्पियो सवार विश्वनाथ देवागन पिता सुखरु देवागन उम्र 43 वर्ष ,राजेंद्र कश्यप पिता कोमल कश्यप उम्र 27 साल (आर्मी जवान) , पोमेश्वर जलतारे पिता पुरषोतम जलतारे उम्र 33 वर्ष (आर्मी जवान) ,भूपेंद्र साहू पिता रेशम साहू 40 साल ,कमलनयन साहू पिता रामचरण साहू उम्र 22साल सभी सडक पारा शांतिनगर नगर पंचायत नवागढ़ निवासी की मौत हो गई वहीं तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गय। इन सभी को तत्काल जिला अस्पताल जांजगीर पहुंचाया गया जिनमें पांच को मृत घोषित करने के साथ तीन घायलों को तत्काल ईलाज के लिए बिलासपुर सिम्स रिफर कर दिया।

घटना में दो आर्मी जवान की हुई मौतज्ज इस घटना में दो आर्मी जवान भी स्कार्पियो में

सवार थे जिनकी मृत्यु हो गई है उनमें राजेन्द्र कश्यप व पोमेशवर जलतारे है जो शादी विवाह में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर नवागढ़ अपने शहर आए हुए थे वहीं इसी हादसे के बाद मृतकों की परिजनों के अलावा पूरे नवागढ़ में मातम छा गया है ।

विधायक कलेक्टर की उपस्थिति में हुआ ज घटना घटित होने के बाद आज सुबह विधायक जिला अस्पताल पहुंचे और मृतकों की परिजनों को ढांढस बंधाया वहीं घंटो तक अस्पताल में ही रहकर मृतकों का पोस्टमार्टम कराया वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने भी वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कर मानवीय संवेदना का परिचय देकर जिला अस्पताल के अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देते रहे।

ट्रक चालक को पुलिस ने पकड़ा – इस हादसे के बाद ट्रक चालक आरोपी अजीत कुमार पिता हरिंदर राय उम्र 23 साल निवासी मूडा थाना गोरखा जिला छपरा (बिहार) मौके से भाग गया था जिसमें एक्सीडेंट की प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय आईपीएस के निर्देशन में थाना जांजगीर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप* के कुशल मार्गदर्शन में फरार ट्रक चालक को पकड़ा जिसको घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से गिरफ्तार विधिवत कार्यवाही की गई।

नगर निगम स्वास्थ्य विभाग जोन की टीमों ने गदगी पाये जाने पर 21 स्थानो पर 12200 रू एवं डस्टबीन नहीं रखने पर 6 दुकानदारो पर 1200 रू कुल 13400 रू. जुर्माना समझाईश देकर वसूला 0

रायपुर -

आज रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देशानुसार नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ तृप्ति पाणीग्रही के नेतृत्व एवं सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों की उपस्थिति में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग जोनो की टीमो द्वारा जनहित में जनस्वास्थ्य सुरुक्षा बाबत सघन अभियान चलाते हुए जोनो में विभिन्न 21 स्थानो पर व्यक्तियो, संस्थाओ से गदगी पाये जाने पर 12200 रू का जुर्माना वसूला एवं 6 दुकानदारो जोन 1 के 4 और जोन 7 के 2 दुकानदारो पर दुकान में समझाईश देने के बाद भी कचरा रखने डस्टबीन ना रखे जाने पर 1200 रू का जुर्माना किया गया। इस तरह कुल 13400 रू. का जुर्माना संबधितो को भविष्य के लिए समझाईश देते हुए वसूला गया। जोन 1 ने 10 व्यक्तियों से 1600 रू. जोन 4 ने 1व्यक्ति से 2000 रू, जोन 6 ने 4 व्यक्तियो से 7400 रू, जोन 7 ने 4 व्यक्तियो से 400 रू एवं जोन 9 ने 4 व्यक्तियो से 1000 रू का जुर्माना गंदगी पाये जाने पर वसूला। नगर निगम स्वास्थ्य विभाग एवं जोनो की टीमो द्वारा जनहित में जनस्वास्थ्य सुख्क्षा हेतु समझाईश देकर गदगी पाये जाने पर और डस्टबीन नहीं रखे जाने पर जुर्माना की कार्यवाही आगे भी निर्देशानुसार जारी रहेगी।

संविधान दिवस पर अधिकार व कर्तव्यों का चर्चा कर संविधान दिवस मनाया गया

जांजगीर चांपा / संविधान दिवस पर जय सतनाम सेवा समिति लछनपुर केराझरिया चांपा द्वारा जोड़ा जय स्तंभ सतनाम भवन गुरु घासीदास स्मारक एवं मिनीमाता सभा स्थल लछनपुर केराझरिया चांपा में 26 नवंबर दिन बुधवार को समय 3:30 बजे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर एवं संविधान किताब के समक्ष दीप प्रज्वलित गुरु आरती ,पुष्प अर्पित कर संविधान दिवस मनाई गई। इस अवसर पर अध्यक्ष संत सोनंत , संरक्षक डॉ ललित कुर्रे , राधे पाटले ,जगमोहनखांडे, सत्यनारायण लहरें , संतोष अनंत , कुमार गौरव मिरी , डॉ धरम लहरे , विधि सलाहकार अधिवक्ता एस के बघेल , डॉ धनेश्वरी जागृति , गेंदराम कुर्रे , कमल जांगड़े आदि ने संविधान दिवस पर विचार रखा विचार रखा । कार्यक्रम में बृजपाल पाटले जय सेवायक राकेश संजय लहरे जोशी सोनू खांन्डे तीज राम अन्य लोग उपस्थित रहे ।संरक्षक डॉ ललित कुर्रे ने संविधान दिवस 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है जिससे संविधान के प्रति जागरूकता सभी धर्म समुदाय को माला की तरह एकरूपता के रूप में बनाए रखना। संविधान दिवस सभी धर्म समुदाय वर्ग को मानना जानना समझना जरूरी है अपने कर्तव्यों का पालन करना व अधिकारों का हनन न होने देना संविधान से जानकारी मिलता है । देश संविधान से चलता है और सभी के लिए प्रावधान उपाय है। संविधान उद्देशिका प्रस्तावना का पाठन कर संकल्प लिया गया। संविधान की अनेक धाराओं पर प्रकाश डाला गया नशा मुक्त समाज पर कार्य कर नवयुवकों को सभ्य समाज बनने आह्वान अपील किया गया। अध्यक्ष संत सोनंत ने सभी का आभार प्रदर्शन किया । उक्त बातों की जानकारी संरक्षक डॉ ललित कुर्रे ने दी।

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने की धान खरीदी प्रगति की समीक्षा

अवैध धान पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश, एग्रीस्टैक पंजीयन को अभियान मोड में करने कहा

जांजगीर-चांपा / कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने जिले में उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से धान खरीदी को सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने एवं प्रगति के संबंध में संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध धान की खरीदी और परिवहन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने कहा कि अगर किसी भी प्रकार की अवैध धान खरीदी या बेचने की जानकारी मिलती है, तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होने कहा कि अवैध धान खरीदी पर अधिकारी विशेष नजर बनाए रखे।

कलेक्टर ने कहा कि सभी किसानों की एंट्री ऑनलाइन गेट पास सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए और केन्द्र में जितने टोकन कटते है तो उन सभी टोकन की एंट्री अनिवार्य रूप से की जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जाएगी, साथ ही अधिकारी सभी किसानों के फोटो के साथ गेट पास में एंट्री होना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि जिले में धान खरीदी का काम किसानों से सीधे जुड़ा हुआ है और इसमें किसी तरह की अड़चन

स्वीकार्य नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि पीडीएस बारदाना का उठाव समय पर किया जाए। बैठक में सतर्क एप के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने सत्यापन कार्य समय पर हो, रकबा समर्पण, तुहर टोकन सहित विभिन्न विषय पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि सभी नोडल अधिकारी सुनिश्चित करे कि सभी खरीदी केंद्रों में पीने का पानी, शौचालय, तौल प्रबंध, कैंपस की सुरक्षा, किसानों के बैठने की व्यवस्था पूर्ण रूप से उपलब्ध रहें। इस अवसर पर खाद्य अधिकारी श्री कौशल साहू सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उपविजेता बनी नेटबॉल टीम का किया सम्मान

जांजगीर-चांपा /

कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने 4वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जूनियर नेटबॉल प्रतियोगिता में उपविजेता बनी जिले की बालक टीम से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिले के युवा खेल के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और यह हम सबके लिए गौरव की बात है। सरगुजा में आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जांजगीर-चांपा की टीम ने शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक अपना दमखम दिखाया। कड़े मुकाबले में टीम दुर्ग से मात्र 1 प्वाइंट के अंतर से पीछे रहकर द्वितीय स्थान पर रही। सम्मान कार्यक्रम में नेटबॉल एसोसिएशन के सचिव श्री राजेश राठौर, कोच श्री शैलेंद्र कहरा, श्री रौशन लाठीया तथा संघ के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास और लक्ष्य के प्रति समर्पण बनाए रखने की प्रेरणा दी।

संविधान दिवस : जिले के शासकीय कार्यालयों एवं स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का किया गया सामूहिक वाचन

जांजगीर-चांपा/

26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर आज कलेक्टोरेट कार्यालय सहित विभिन्न शासकीय कार्यालयों एवं स्कूलों के छात्र-छात्राओं और विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक रूप से वाचन किया। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारी-कर्मचारियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया और संविधान से संबंधित विभिन्न जानकारियां भी दी गई। उल्लेखनीय है कि 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। प्रति वर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस का उद्देश्य नागरिकों को संविधान की मूलभूत धारा और उद्देश्य से अवगत कराना है। जिले में संविधान दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

खास खबर

अमीन भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर को

कोरबा। छ0ग0 व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित अमीन भर्ती परीक्षा 07 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 02.15 बजे तक जिले के 31 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जायेगी। जिसमें कुल 09 हजार 502 परीक्षार्थी शामिल होंगे। संयुक्त कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी ने बताया कि परीक्षा के सफल संचालन हेतु व्यापम के निर्देषों के तहत सभी आब्जर्वर, केन्द्राध्यक्ष एवं उड़नदस्ता दल को विस्तृत प्रषिक्षण दिया जायेगा। परीक्षार्थियों के लिये निर्देष जारी किया गया है कि परीक्षा दोपहर 12 बजे से 02.15 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व 11.30 बजे बंद कर दिया जायेगा। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 02 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचेंगें ताकि सभी अभ्यर्थिओं का मेटल डिटेक्टर तथा प्रिस्किंग जांच किया जा सके। परीक्षार्थी को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनना होगा। फूट बियर के रूप में चप्पल पहनेंगे। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रानिक उपकरण, इलेक्ट्रानिक घड़ी, पर्स, पाउज, स्कार्फ बेल्ट, दोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जायेगी। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोषाक वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। भारत इलेक्ट्रानिक लिमिटेड द्वारा सभी केन्द्रों में जैमर लगाया गया है।

कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर, संवाददाता।

जिले की कोनी थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त किया है। मामले में आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अवैध शराब का धंधा करने वाले एवं खरीदी बिक्री करने वालों के ऊपर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु दिशा निर्देश दिए गया हैं जिसके अनुक्रम में दिनांक 23/11/2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति लच्छनपुर से कच्ची महुवा शराब लेकर ग्राम अमतरा की ओर आ रहा हैं सूचना तस्दीक व अग्रिम कार्यवाही हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिशानिर्देश प्राप्त कर ग्राम अमतरा नहर के पास घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसके कब्जे से 05- 05 लीटर के प्लास्टिक जरीकेन में कुल 10 लीटर कच्ची महुवा शराब मिला नाम पता पूछने पर भागीरथी पाटले पिता नारायण पाटले उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम अमतरा थाना कोनी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला बताया शराब रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं करने पर 10 लीटर अवैध हाथ भट्टी से निर्मित कच्ची महुआ शराब को समक्ष गवाहन जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया ।

रायगढ़ जिले में अब तक 2.26 करोड़ का 7300 क्विंटल धान जब्त

लोकशक्ति

रायगढ़ रायगढ़ जिले में धान खरीदी की महाभियान के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है। जिले में अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर रायगढ़ जिले में अब तक 43 प्रकरणों में 7300 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ 26 लाख रुपए से अधिक है। वहीं पिछले 5 दिनों में 12 प्रकरणों में 3986 क्विंटल धान जब्त किया है, जिसकी 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कीमत 1 करोड़ 23 लाख 55 हजार रुपए से अधिक है। इन कार्रवाईयों में अंतर्राज्यीय बेरियर रेंगालपाली, जमुना और पुसौर के लारा बेरियर शामिल है। साथ ही 40 कोचियों पर कार्रवाई की गई। सभी प्रकरणों को छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है।

कलेक्टर ने धान के अवैध परिवहन और भण्डारण पर लगातार कार्रवाई करने के लिए जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और संबंधित संयुक्त टीम को दिए है। साथ ही उपार्जन केन्द्र पर नियुक्त नोडल अधिकारियों को भी सतत् मॉनिटरिंग करने और उसकी सूचना उच्चाधिकारियों को देने के निर्देश दिए है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में कोचियों व बिचौलियों द्वारा अवैध धान खपाने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है। अंतर्राज्यीय व आंतरिक चेकपोस्टों पर अधिकारी-कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीमें लगातार फील्ड में सक्रिय है। उपार्जन केंद्रों में सीसीटीवी निगरानी से रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और संदेहास्पद वाहनों की अनिवार्य जांच की जा रही। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए जिले में सख्त कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी।

रायगढ़ जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में संयुक्त जांच दल द्वारा बड़ी मात्रा में अवैध धान जब्त किया गया। पिछले 5 दिनों में 12 प्रकरण धान के अवैध भण्डारण एवं परिवहन के प्रकरण दर्ज किया गया है। इनमें घरघोड़ा विकासखंड के ग्राम-कुर्मीभौना में दुर्गेश बेहरा के पास 8 क्विंटल धान जब्त किया गया। इसी तरह धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम पुरुंगा में रतनलाल साहू से 150 क्विंटल, ग्राम बायसी में नरेश निषाद के पास से 52 क्विंटल धान जब्त किया गया। रायगढ़ विकासखंड के ग्राम कछार में रोहित पटेल के पास 160 क्विंटल, ग्राम लोइंग के नोहर पटेल के पास 100 क्विंटल, विद्यानंद पटेल-120 क्विंटल एवं सूरत पटेल से 200 क्विंटल, ग्राम बालमगोडा में कन्हैया पटेल के पास 40 क्विंटल, ग्राम महापल्ली में मनीष अग्रवाल के गोदाम से 2600 क्विंटल धान जब्त किया गया। खरसिया विकासखंड के ग्राम-साजापाली में धरणीधर गबेल, के पास 20 क्विंटल, पुसौर विकासखंड के ग्राम नेतनागर में मंगल साहू के पास 500 क्विंटल, तमनार विकासखंड के ग्राम केसरचुआ में रामप्रसाद राठिया के पास 34.80 क्विंटल धान जब्त किया गया। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि सभी मामलों में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। किसानों के हितों की रक्षा और अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए यह सख्त अभियान इसी तरह जारी रहेगा।

26 को व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा संविधान दिवस

विविध गतिविधियों का होगा आयोजन

कोरबा

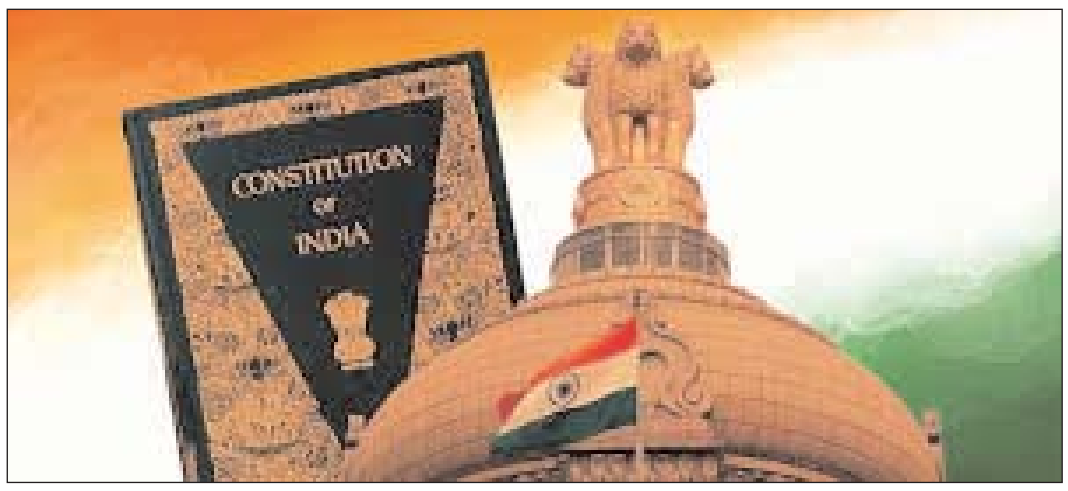

कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 26 नवम्बर को भारत का संविधान अपनाए जाने के स्मरणोत्सव स्वरूप जिले में व्यापक स्तर पर संविधान दिवस मनाने के निर्देश दिए है। इस अवसर पर हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमानष् विषय पर पूरे वर्ष विशेष उत्सव का आयोजन किया जाएगा।

इस हेतु कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को संविधान दिवस मनाने के सम्बंध में विशेष निर्देश जारी किए है। जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में 22भाषाओं में सामूहिक प्रस्तावना का वाचन () किया जाएगा। साथ ही प्रदर्शनी वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध) का आयोजन,

फिल्म की स्क्रीनिंग एवंऑनलाईन संविधान दिवस क्विज में हिस्सा लेना (डलळवअ.पद) जैसी गतिविधियें का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर ने जिला हेडक्वार्टर, तहसील, पंचायत और गांवो में बड़े पैमाने पर प्रस्तावना पाठ कर सभी वी यों, कें पन वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश दिए है। प्रस्तावना पढ़ने और अपलोड करने की सुविधा कई भाषा में आनलाईन उपलब्ध है। राज्य के नागरिकों को अकेले या साथ मिलकर प्रस्तावना पढ़ने और कैं पेन वेबसाइट पर विडियों अपलोड किया जाएगा। बड़े पैमाने पर प्रस्तावना पढ़ने के साथ-साथ शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाएंगे। डमपजल डलळवअ.पद पर 22 भाषाओं में डिजिटल तरीके से शपथ लेने का समारोह आयोजित कर उक्त आयोजन में सभी को सम्मिलित होने हेतु प्रोत्साहित किए जाएंगे। राज्य के स्कूल और कॉलेज में भारत के संविधान को समर्पित खास असेंबली का आयोजन करने निर्देशित किया है। प्रस्तावना की वॉल आर्ट स्कूलों, पंचायतों, सहकारी, ऑफिस और अन्य पब्लिक जगहों पर बनाई जाएं। प्रस्तावना के बॉर्डर डिजाइन की ओपन फाईल से डाउनलोड की जा सकती है। कैंपेन के लिए प्रदर्शनी, फिल्मी, लोगों तथा अन्य सामग्री वेबसाइट पर उपलब्ध है।

महिला आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों की सुनवाई 27 को

कोरबा 25 नवम्बर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक एवं न्याय पीठ द्वारा कोरबा जिले से प्राप्त शिकायतों की सुनवाई 27 नवंबर को प्रातः 11 बजे कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष कोरबा में मे नियत की गई है।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अग्रवाल नहीं रहे..

कोरबा 25 नवम्बर। कोरबा अंचल के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं जिला अधिवक्ता संघ कोरबा के संस्थापक सदस्यों में से एक राधेश्याम अग्रवाल का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से परिजन, मित्र, रिश्तेदार, अधिवक्ताओ, अग्रवाल समाज सहित अंचल में शोक व्याप्त हो गया हैं। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया की उनका अंतिम संस्कार आज 25 नवंबर को किया जाएगा।

कामता प्रसाद सिंह का निधन

कोरबा । आर पी नगर निवासी रिटायर्ड एसईसीएल कर्मी कोरबा निवासी श्री कामता प्रसाद सिंह (80) का 24 नवंबर 2025 को निधन हो गया है। श्री कामता प्रसाद सिंह अपने सामाजिक ,सेवाभावी और सरल स्वभाव के लिए क्षेत्र में जाने जाते थे। उनके निधन से परिवार, मित्रगण और परिचितों में शोक की लहर है। शोक संतप्त में पुत्र नरेंद्र कुमार सिंह, सुबोध कुमार सिंह अध्यक्ष ,जिला टिप टेलर एसोसिएशन , शशांक सिंह, शिवम सिंह सहित भरपुरा परिवार शामिल है।

जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की शासी परिसद की बैठक 06 दिसंबर को

कोरबा । कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की अध्यक्षता में जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की शासी परिषद की बैठक 06 दिसंबर को प्रातः 11 बजे कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष कोरबा में आयोजित की गई है।

नगर में विद्युत पोल के बीच केबल, तारों के जाल में फंसकर विद्युत व्यवस्था चरमराई

बिलासपुर, नगर में जहाँ तहाँ बीच-बीच में बीच मुख्य सड़कों पर बिजली के खंभों पर लगे केबल व तारों के मकड़जाल बिजली व्यवस्था का मुंह चिढ़ा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद कुछ दिनों तक तारों को व्यवस्थित किया गया है, लेकिन दोबारा शहर की सड़कों पर एक बार फिर केबल और तार दिखाई देने लगे है। बिजली के ढीले तार, उलझे हुए तारों के कारण आए दिन शॉर्ट सर्किट और आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ दिनों में शहर के कई हिस्सों जैसे महाराणा प्रताप चौक, लिंक रोड, व्यापार विहार, मंगला, मसानगंज, जूनी लाइन, तालापारा, जूना बिलासपुर और सरकंडा क्षेत्र में तारों के जाल दिखाई दें रहे हैं। इसके चलते शॉर्ट सर्किट की घटनाएं सामने आती हैं। ज्यादातर खंबों में लैंड लाइन, टीवी केबल, फाइबर केबल के जाल हैं। वहीं पुराने और जर्जर तारों का भी उचित प्रबंधन नहीं किया गया है। कुछ माह पहले कोर्ट के निर्देश के बाद बिजली अधिकारियों ने केबल हटाया था, लेकिन एक बार फिर शहर की सड़कों पर केबल व तारों के जाल दिखने लगे है। **ठोस योजना नहीं** जानकारों के मुताबिक कुछ साल पहले स्मार्ट सिटी के तहत सड़कों पर फैले तारों के जालों को व्यवस्थित करने की योजना बनाई गई थी लेकिन यह ठंडे बस्ते में जा चुकी है।

कलेक्टर का औचक निरीक्षण : कई विभागों में अधिकारी-कर्मचारी नदारद, उद्योग विभाग में केवल चपरासी मिला

बिलासपुर, संवाददाता

सुबह 10 बजे कलेक्टर संजय अग्रवाल ने न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग स्थित कई विभागों का अचानक निरीक्षण किया, जिसमें लापरवाही की बड़ी तस्वीर सामने आई। बिना पूर्व सूचना किए गए इस औचक जांच में कई दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर कलेक्टर ने कड़ा असंतोष जताया।

प्रशासन ने हाल ही में कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन अवकाश (शनिवारङ्करविवार) का लाभ देते हुए दफ्तर का समय सुबह 10 बजे तय किया है। इसके बावजूद कई कर्मचारी पुराने ढर्रे पर चलते हुए अब भी 11 बजे के बाद पहुंच रहे हैं। इसी व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए कलेक्टर अग्रवाल ने निरीक्षण किया।

सबसे खराब स्थिति उद्योग विभाग में दिखी, जहां निरीक्षण के दौरान केवल एक चपरासी मौजूद था।

कोषालय एवं लेखा विभाग में तो चपरासी तक नहीं मिला, जिससे कलेक्टर का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा– जब वेतन कटेगा, तब समय की कीमत समझ आएगी। मौके पर ही उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर मंगवाकर जांच की। इसके विपरीत, श्रम विभाग में अनुशासन का बेहतर उदाहरण देखने मिला। कुल 37 में से 35 कर्मचारी समय पर उपस्थित थे। श्रमायुक्त ने बताया कि बायोमैट्रिक उपस्थिति लागू होने के बाद ही समय पालन में सुधार आया है। कलेक्टर ने अन्य विभागों को श्रम विभाग की कार्यप्रणाली से सीख लेने की सलाह दी। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि कई विभाग बायोमैट्रिक मशीन होने के बावजूद इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस पर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने निर्देश दिए कि सभी कार्यालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य रूप से लागू की जाए और किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

कटघोरा क्षेत्र में संयुक्त दल की कार्रवाई, 90 क्विंटल अवैध धान जप्त

कोरबा (संवाददाता)।

कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देशानुसार तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तन्मय खन्ना (आईएएस) के मार्गदर्शन में 24 नवम्बर 2025 को कटघोरा क्षेत्र में अवैध धान भंडारण पर सख्त कार्रवाई की गई। तहसीलदार कटघोरा सूर्यप्रकाश केशकर, खाद्य निरीक्षक सुरेन्द्र लांझी, तथा कृषि उपज मंडी समिति कटघोरा के सहायक ग्रेड-2 राजेश झारिया से गठित संयुक्त जांच दल ने विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं गोदामों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान कटघोरा, छिर्रा एवं पुरानी बस्ती क्षेत्र में कई व्यापारियों के दुकान सह गोदामों में अवैध रूप से भंडारित धान पाया गया। जांच दल द्वारा नियमों के तहत धान को जप्त कर मंडी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार आगे की कार्रवाई की गई तथा जप्त धान को विधिवत सुपुर्दगी में दिया गया।

जांच के दौरान कटघोरा क्षेत्र के व्यापारी दिलीप कुमार अग्रवाल के पास 16.80 क्विंटल, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल के पास 11.20 क्विंटल, छिर्रा के भागवत प्रसाद जायसवाल के पास 16 क्विंटल तथा कटघोरा की पुरानी बस्ती के यतीश जायसवाल के पास 46 क्विंटल धान अवैध रूप से संग्रहित पाया गया।

कुल 90 क्विंटल धान जप्त किया गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य व्यवस्था को सुचारू एवं पारदर्शी बनाए रखने के लिए अवैध भंडारण तथा अनियमितताओं के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्रशासन ने व्यापारियों एवं नागरिकों से नियमों का पालन करने एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तत्काल उपलब्ध कराने की अपील की है।

किसान मंगली बाई धान खरीदी को लेकर है उत्साहित

कोरबा । जिले के पाली ब्लॉक के अंतिम छोर से लगे ग्राम सिस की कृषक मंगली बाई इस वर्ष होने वाली धान खरीदी को लेकर विशेष उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के सभी सदस्य खेती-किसानी के कार्यों में मिल-जुलकर सहयोग करते हैं। परिवार के सदस्य प्रदीप कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर लगभग 102 क्विंटल धान की बिक्री कर परिवार को अच्छी आमदनी हुई थी। समय पर मिले भुगतान ने खेती को मजबूती देने के साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति को भी स्थिर किया। इस समय खेतों में धान कटाई के कार्य जारी हैं और मंगली बाई अपने परिवार के साथ फसल का मूल्यांकन कर रही हैं। घर के आंगन में मिंजाई का काम चल रहा है और पूरे परिवार के चेहरों पर इस वर्ष की खरीदी को लेकर नई उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। मंगली बाई ने बताया कि पिछले वर्ष समय पर भुगतान मिलने से उन्होंने खेती के लिए बेहतर बीज, खाद और अन्य आवश्यक कृषि सामग्री खरीद पाई। साथ ही परिवार की दैनिक जरूरतें भी आसानी से पूरी हो सकीं। इस वर्ष भी उन्हें उम्मीद है कि धान खरीदी से बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान का सर्वाधिक खरीदी मूल्य, डीबीटी के माध्यम से त्वरित भुगतान, और खरीदी केंद्रों के बेहतर प्रबंधन ने किसानों के बीच भरोसा और उत्साह बढ़ाया है।

राजभवन सचिवालय के अधिकारियों-कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का किया वाचन

रायपुर, संविधान दिवस के अवसर पर राजभवन सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था। राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर प्रसन्ना, विधिक सलाहकार श्री भीष्म प्रसाद पाण्डेय सहित सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया।

भाठागाँव में संकीर्तन-भजन स्मृति कार्यक्रम, भक्तिमय माहौल में उमड़ा घासी-घसिया समाज

संवाददाता। **रायपुर,** राजधानी रायपुर के बीएसयूपी कॉलोनी, भाठागाँव में घासी-घसिया समाज द्वारा संकीर्तन भजन स्मृति शेष नमन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ और ओड़िशा से आई विभिन्न भजन-कीर्तन मंडलियों ने अपनी प्रस्तुति से वातावरण को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। भजन और कीर्तन की सुर लहरियों पर समाजजन भाव-विभोर होते दिखाई दिए।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) छत्तीसगढ़ के प्रदेश संगठक एवं रायपुर जिला अध्यक्ष राहुल सिंह परिहार ने समाज की सांस्कृतिक जड़ों, आध्यात्मिक परंपराओं और नैतिक मूल्यों की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को भक्ति, सत्संग और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने और आदर्श जीवन मूल्यों को बचाए रखने के लिए भजन-कीर्तन एक प्रभावी मार्ग है। इस अवसर पर समाज के प्रदेश अध्यक्ष लखन सागर और रायपुर जिला अध्यक्ष गोपी सेंद्रे ने 'स्मृति शेष नमन' की भावनात्मक पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम उन पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम है, जिन्होंने इस परंपरा को संरक्षित रखा और समाज को आध्यात्मिक दिशा दी। उन्होंने समाज को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने की अपील की।

वन विभाग द्वारा दो सॉ मिलों को किया गया सील

कोण्डागांव, वनमंडलाधिकारी कोंडागांव चूणामणी सिंह, भा.व.से के निर्देशानुसार एवं सयुक्त वनमंडलाधिकारी कोंडागांव आशीष कोट्रीवार के मार्गदर्शन में कोंडागांव वनमंडल अंतर्गत संचालित आरामिल जोगेन्दर सॉ मिल एवं शारदा विजय सॉ मिल कोंडागांव पर कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में राज्य स्तरीय उडनदस्ता दल की उपस्थिति में की गई। दोनों सॉ मिल के संबंध में राज्य स्तरीय उडनदस्ता दल को शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिना वैद्य उत्तराधिकारी के इसका संचालन किया जा रहा है। उक्त दोनो सॉ मिल पर छत्तीसगढ काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 की धारा 8, 9 एवं 10 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये आगामी आदेश तक सील किया गया है।

स्कूलों के प्राचार्यों को सौंपी गई आवारा कुत्तों की पहचान और रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी

रायपुर,(आरएनएस)। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूल परिसरों और आसपास घूम रहे आवारा कुत्तों को लेकर नया निर्देश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब विद्यालयों के प्राचार्य और प्रधान पाठकों को कुत्तों की पहचान, विवरण जुटाने और उसकी रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए एक निर्धारित फार्मेट भी जारी किया गया है, जिसे हस्ताक्षर सहित जमा करना अनिवार्य होगा। जारी प्रपत्र में संस्था प्रमुखों को क्रमांक, स्कूल का नाम, संकुल, विकासखंड, जिला, कुत्तों का प्रकार, नर/मादा, रंग, विशेष पहचान और कुत्तों को देखने का समय जैसी जानकारियां भरनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों की धरपकड़ संबंधी निर्देशों के बाद पशुधन विकास विभाग ने रणनीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। स्कूलों के आसपास कुत्तों की मौजूदगी से बच्चों के काटे जाने की घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आदेश के पालन और समीक्षा की जिम्मेदारी जेडी और डीईओ अधिकारियों को सौंपी गई है। DPI द्वारा फार्मेट जारी होने के साथ ही स्कूल स्तर पर जानकारी संकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

अनाधिकृत रूप से भंडारित पाए जाने पर 150 क्विंटल धान जप्त

गौरेला पेंड्रा मरवाही, (आरएनएस)। मरवाही विकासखण्ड के ग्राम खुरपा के लम्नाटोला में दो सगे भाई नारद भैना और व्यास भैना के घर अनाधिकृत रूप से भंडारित पाए जाने पर लगभग 150 क्विंटल धान जप्त कर गांव के सरपंच की देख-रेख में उनके सुपुर्द किया गया है। कलेक्टर के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी के दौरान बिचौलियों द्वारा अनाधिकृत रूप से धान का परिवहन एवं भंडारण कर उपार्जन केंद्रों में खपाए जाने पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एसडीएम मरवाही श्री देवेन्द्र सिरमौर ने बताया कि सूचना मिलने पर खुरपा के लम्नाटोला में जांच के दौरान अनाधिकृत रूप से धान भंडारित पाए जाने पर जप्ती की कार्रवाई की गई है।

पुलिस हिरासत में बंद तोमर की जमानत याचिका खारिज

रायपुर, (आरएनएस)। राजधानी में ब्याज पर धंधा करने वाले एवं गरीबों को लूटने वाले विरेन्द्र तोमर को पुलिस हिरासत में रखा गया है। विरेन्द्र ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए एक याचिका लगाई थी जिसके खारिज कर दिया गया है। ज्ञात रहे कि पुलिस ने तोमर बंधुओं को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था।उसे राजधानी लाया गया जहां पर उसका जुलूस निकाला गया।

जिला अस्पताल सुकमा में मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशनों से दिख रही रोशनी की नई किरण जिला अस्पताल सुकमा में

लोकशक्ति
रायपुर, संवाददाता

जिला अस्पताल सुकमा में मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार विशेष पहल की जा रही है। कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन में सुकमा जिले के अंदरूनी, पहाड़ी और पहुंचविहीन क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को जिला अस्पताल में लाकर निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर. के. सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. गीतु हरित और अंधत्व नोडल अधिकारी डॉ. प्रवीण टेली के सहयोग से मरीजों को घर से अस्पताल लाने और ऑपरेशन के बाद उन्हें दोबारा सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था भी जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की गई है। अस्पताल में मरीजों सहित उनके अटेंडर और मितानिनों के लिए ठहरने और भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच उपलब्धि

अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच जिला अस्पताल सुकमा में दोनों आँखों के 93 मरीजों तथा एक आँख के 129 मरीजों का सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया है। इससे सैकड़ों लोगों को दृष्टि सुधार का लाभ मिला है।

शासन के निर्देशानुसार स्कूलों में भी नेत्र परीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अब तक कुल 439 छात्र-छात्राओं में दृष्टि दोष पाया गया है, जिन्हें शीघ्र ही निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा 40 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में दृष्टि दोष की पहचान कर 197 लोगों को निःशुल्क प्रेसबायोपिक चश्मे प्रदान किए गए हैं।

नियद नेल्ला नार क्षेत्र में बड़ा नेत्र सुरक्षा अभियान विकासखंड कोंटा के अत्यंत संवेदनशील और आंतरिक क्षेत्र में 24 सितंबर 2025 से 01 अक्टूबर 2025 तक व्यापक नेत्र सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला सुकमा की नेत्र टीम, एमपीडब्ल्यू, सुपरवाइजर एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने नियद नेल्ला नार के क्षेत्र सहित कोण्डासांवली, सिलगेर, जगरगुण्डा, तिम्मापुरम, सुरपनगुड़ा, कुण्डेल, बिकरमपल्ली, तारलागुड़ा, कामाराम, सिंगावरम, तुमलपाड़, पुलनपाड़, नरसापुरम, उरसंलग, गोंदपल्ली, बुर्कापाल, तोंगपल्ली, नागाराम, केरलापेंदा, कोलाईगुड़ा, पिड़मेल,टेकलगुड़ा, जुनागुड़ा, दुलेड़, एलमागुण्डा, तोकनपल्ली, गच्छनपल्ली, बुर्कालंका, मुरलीगुड़ा, किस्टाराम, पोटकपल्ली, तिगनपल्ली, सिंदुरगुड़ा, गोगुण्डा, परिया सहित कई गांवों का सर्वेक्षण किया।

सर्वेक्षण में दोनों आंखों से मोतियाबिंद से ग्रसित 492 मरीज तथा एक आंख से ग्रसित 132 मरीज पाए गए हैं। इन सभी मरीजों को शीघ्र ही जिला अस्पताल लाकर उनका ऑपरेशन कराया जाएगा। शासन-प्रशासन का उद्देश्य है कि सुकमा के अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुंचें और कोई भी मरीज उपचार से वंचित न रहे। दूरस्थ वनांचलों में लगातार सर्वेक्षण, मरीजों की सुरक्षित परिवहन व्यवस्था, अस्पताल में रहने-खाने की सुविधा और निःशुल्क ऑपरेशन से यह अभियान जिले में नेत्र स्वास्थ्य सुरक्षा की मिसाल बन रहा है।

भाजपा पश्चिम नगर मण्डल ने मनाया मितानीन दिवस

जगदलपुर, भाजपा पश्चिम नगर मंडल द्वारा मितानिन दिवस मनाते हुये मितानीन कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। स्थानीय गंगा नगर वार्ड के माड़िया सराय भवन में कार्यक्रम आयोजित कर मितानिन बहनों को शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुये।

भाजपा जिला महामंत्री रजनीश पाणिग्रही, परीसराम बेसरा और पश्चिम नगर मण्डल अध्यक्ष प्रकाश झा ने मितानीन दिवस की शुभकामनाएँ देते हुये मितानीन कार्यकर्ताओं के सेवा कार्य की सराहना की। मितानीन दिवस के आयोजन में सुमित्रा कश्यप (मितानिन ट्रेनर), नवीन कुरैशी (क्षेत्रीय समन्वयक), सुमनी ठाकुर, पार्वती नाग, जुबेदा बेगम, मालती ठाकुर, कनेश्वरी साहू, रेखा उपाध्याय, रजनी सोनी, धनिता साहू, अंविका यादव, मनीषा चौधरी, चंद्रा शर्मा, दीपा बघेल, रुनझुन ठाकुर का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला मंत्री रैतु राम कश्यप, नगर मण्डल महामंत्री संजय चंद्राकर, जिला कार्यालय सह-प्रभारी राजपाल कसेर, सोशल मीडिया प्रभारी ब्रिजेश शर्मा, नगर मंडल कोषाध्यक्ष एवं पार्षद आशा साहू, युवा मोर्चा सदस्य अभिषेक तिवारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर लंगेह ने विभिन्न धान उपार्जन केन्द्रों एवं अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट का किया निरीक्षण

महासमुंद के 155 केन्द्रों में 2 लाख 5 हजार 453 क्विंटल धान की खरीदी

0 वहीं राज्य में सर्वाधिक 51 प्रकरणों में 5071 क्विंटल धान जप्त

महासमुंद, लोकशक्ति

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज महासमुंद के बिरकोनी एवं सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत प्राथमिक कृषि एवं साख समिति जंगलबेड़ा, सिरबोड़ा, कुसमीसरार, तोरेसिंहा और अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट सिरपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धान उपार्जन केंद्रों में धान बेचने आए किसानों से चर्चा कर उनसे धान उपार्जन केंद्र में लाये गये धान की मात्रा, धान का उत्पादन के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने किसानों द्वारा आज जारी टोकन के विरुद्ध लाई गई धान की आवक में नमी की जांच प्रक्रिया का अवलोकन किया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अधिक नमी वाले धान को स्वीकार न किया जाए तथा नमी परीक्षण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने केंद्र में 100 प्रतिशत गेट पास एंट्री अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आज की तिथि तक खरीदे गए धान की कुल मात्रा तथा उसके अनुरूप जारी किए गए बारदाने का भौतिक सत्यापन भी कराया गया। इन केन्द्रों में उन्होंने किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए धान खरीदी केंद्र में स्थल की साफसफाई, पेयजल, किसानों के बैठने हेतु छायादार स्थान, त्रुटिरहित धान खरीदी हेतु कांटा-बांट अथवा इलेक्ट्रॉनिक कांटा का सत्यापन आदि का जायजा लिया। साथ ही उपार्जन केंद्रों में कैप कवर, बारदाने की व्यवस्था, कम्प्यूटर सेट, प्रिंटर, इंटरनेट सुविधा सहित अन्य व्यवस्थाएं भी देखी। इसके अलावा कलेक्टर ने प्राधिकृत अधिकारी को पर्याप्त संख्या में हमाल उपलब्ध कराने, प्रतिदिन खरीदी गई मात्रा का नियमित स्टैकिंग करने तथा प्रत्येक बोरे पर अनिवार्य रूप से स्टेंसिल लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि खरीदी कार्य सुचारू, पारदर्शी और किसानों के हित में संचालित हो, इसके लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने सभी नोडल अधिकारियों को धान खरीदी केन्द्र में सतत निगरानी रखते हुए धान खरीदी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को धान खरीदी कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों में कोचियों एवं बिचौलियों से अवैध धान की खरीदी-बिक्री पर सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है।

माकड़ी ब्लॉक में 100 पीएम सूर्य घर का सफल इंस्टालेशन

कोण्डागांव जिला बन रहा सौर ऊर्जा का नया हब

कोण्डागांव, कोंडागांव जिले का माकड़ी ब्लॉक आज पूरे बस्तर संभाग में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया केन्द्र बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर सोलर विज़न को वास्तविक रूप देने वाली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने इस क्षेत्र में न केवल सुलभ ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित की है, बल्कि इससे ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव आया है। डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर मॉकडी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 100 घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम को सफलतापूर्वक ग्रिड से सिंक्रोनाइज करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है, जो साबित करती है कि दूरस्थ और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा अपनाने की जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब तक जिले में कुल 284 घरों में सोलर पैनल लग चुका है, जिसमें 50 से अधिक इंस्टॉलेशन सिर्फ ग्राम माकड़ी में ही किए गए हैं।उक्त योजना के तहत घरों की छतों पर स्थापित सोलर पैनल से घरेलू खपत की पूर्ति में सक्षम होते हैं और बिजली की अतिरिक्त उत्पादन से आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल की सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र और राज्य शासन की संयुक्त सब्सिडी ने ग्रामीण परिवारों के लिए सोलर सिस्टम लगवाना बेहद आसान कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली बड़ी सब्सिडी के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य शासन भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह सब्सिडी सीधे डीबीटी के माध्यम से उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा होती है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और भरोसेमंद बन गई है।माकड़ी ब्लॉक में सौर ऊर्जा अपनाने के बाद परिवारों के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आए हैं।

जशपुर में क्लिक सेफ साइबर जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

छात्राओं को ऑनलाइन सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों पर किया गया शिक्षित

जशपुर, (संवाददाता)। **जशपुर पुलिस** ने यूनिसेफ के सहयोग से साइबर सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता पर केंद्रित क्लिक सेफ कार्यक्रम का आयोजन किया। यह सत्र शासकीय पोस्ट मैट्रिक बालिका छात्रावास में आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं को ऑनलाइन अपराध, धोखाधड़ी से बचाव और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार की जानकारी दी गई। इसके साथ ही बालिकाओं को लैंगिक समानता, मानव तस्करी, बाल विवाह और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर भी मार्गदर्शन दिया गया। वर्तमान समय में मोबाइल और ऑनलाइन लेन-देन के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी उद्देश्य से जशपुर पुलिस ने यूनिसेफ के साथ मिलकर साइबर स्वयंसेवकों की टीम तैयार की है, जो हाट-बाजार, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों में लोगों को जागरूक कर रही है। कार्यक्रम के दौरान साइबर सेल की ओर से डीएसपी (अजाक) भावेश समरथ ने छात्राओं को ऑनलाइन ठगी के तौर-तरीकों, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने सलाह दी कि

अनजाने लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें -यूनिसेफ की जिला समन्वयक शालिनी गुप्ता ने लिंग भेदभाव, बॉडी शेमिंग, बाल विवाह और मानव तस्करी के सामाजिक प्रभावों पर जानकारी देते हुए आत्मविश्वास और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया।

जशपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि संदिग्ध लिंक, कॉल या ईमेल पर भरोसा न करें केवल सुरक्षित और प्रमाणित वेबसाइट का उपयोग करें दो-स्तरीय सुरक्षा (2स्त्र) अपनाएं सार्वजनिक वाई-फाई पर लेन-देन न करें बैंक संबंधी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करें। ऑनलाइन गतिविधियों की नियमित निगरानी करें।

सायबर अपराध की स्थिति में तत्काल:

हेल्पलाइन 1390 पर संपर्क करें

निकटतम थाने या साइबर सेल को सूचित करें कार्यक्रम में डीएसपी भावेश समरथ, यूनिसेफ समन्वयक शालिनी गुप्ता, छात्रावास अधीक्षक मीना प्रधान सहित पुलिस स्टाफ, हॉस्टल कर्मचारी और छात्राएं उपस्थित रहीं।

जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य सतत रूप से जारी

महासमुंद,। छत्तीसगढ़ राज्य में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 04 नवम्बर 2025 से शुरू हो चुका है। इसी क्रम में महासमुंद जिले के चारों विधानसभा सरापाली-39, बसना-40, खल्लारी-41 एवं महासमुंद-42 में कुल 1083 बीएलओ द्वारा निर्वाचक गणना प्रपत्रों का लगभग शत प्रतिशत वितरण पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही जिले में प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो अब तक 52 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह ने सभी बीएलओ को एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जिले में कुल 8 लाख 86 हजार 422 मतदाता पंजीकृत है, इनमें 8 लाख 77 हजार 556 मतदाताओं के घर-घर जाकर निर्वाचक गणना प्रपत्रों का वितरण एवं सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है। जिसमें सरायपाली विधानसभा अंतर्गत 2 लाख 14 हजार 204 मतदाता, बसना में 2 लाख 28 हजार 143, खल्लारी में 2 लाख 21 हजार 533 एवं महासमुंद विधानसभा अंतर्गत 2 लाख 13 हजार 676 मतदाता शामिल है। साथ ही अब तक 4 लाख 63 हजार 546 गणना पत्रक डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। जिसमें सरायपाली अंतर्गत 58 प्रतिशत, बसना अंतर्गत 61.34 प्रतिशत, खल्लारी अंतर्गत 55 प्रतिशत एवं महासमुंद अंतर्गत 33.89 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है।

कलेक्टर ने सराहनीय कार्य करने वाले बीएलओ को किया सम्मानित

रायपुर, । कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया। आरंग विधानसभा क्षेत्र - 52 की बूथ लेवल अधिकारी श्रीमती टिकेश्वरी साहू मतदान केन्द्र 58 परसकोल, श्रीमती सोहद्रा साहू मतदान केन्द्र 132 रानीसागर, श्रीमती जानी चंद्राकर मतदान केन्द्र 133 देवरी एवं श्रीमती धनेश्वरी बंजारे मतदान केन्द्र 112 कुरूद बीएलओ द्वारा समय पूर्व शत् प्रतिशत कार्य पूर्ण किया गया है।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)